हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 21 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(7) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 2
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 20
जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में गांव इगरा से दो अपहृत लड़कियों के अपहरण का मामला उठाना	(7) 40
सदन के कार्य में परिवर्तन	(7) 41
वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(7) 41

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

स्वतन्त्रता सेनानी

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री शीश राम यादव, गांव रामपुरा, जिला झज्जर के 19 मार्च, 2016 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

वीर सैनिक

यह सदन लांस नायक सतेन्द्र सिंह चौहान, गांव रतनथल, जिला रेवाड़ी के 13 मार्च, 2016 को हुए दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वश्री शीशराम यादव, स्वतंत्रता सेनानी एवं लांस नायक सतेन्द्र सिंह चौहान के दु:खद निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है। मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं तथा इन दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति दु:ख प्रकट करता हूँ।

मैं परमपिता परमात्मा से इन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूं और इन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी।

अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

———————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल होगा।

Rajiv Gandhi Scheme

***1386. Smt. Prem Lata :** Will the Women and Child Development Minister be pleased to state whether the Government is implementing the Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of adolescent girls (Sabla); if so, the details thereof togetherwith the fund allocated and utilized alongwith the number of beneficiaries under this scheme during each of the last three years ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हाँ श्रीमान जी। सम्बन्धित सूचना निम्न तालिका में वर्णित है :—

तालिका-I

आबंटित राशि व खर्चा

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	वर्ष	राशि प्राप्त		खर्च की गई राशि	
		पोषण	गैर-पोषण	पोषण	गैर-पोषण
1	2012-13	1000.00	120.42	877.56	120.34
2	2013-14	1540.30	81.86	1220.04	19.29
3	2014-15	1511.98	136.47	1378.90	128.87

तालिका-II

पिछले तीन वर्षो के दौरान लाभार्थियों का विवरण :-

क्र0सं0	घटक	लाभार्थियों की संख्या		
क	पोषण	2012-13	2013-14	2014-15
ख	गैर-पोषण	145519	136934	150065
1	आयरन फौलिक एसिड अनुपूरण	24088	23770	19318
2	स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं	24088	23770	19318
3	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	69193	54701	34272
4	परामर्श/मार्गदर्शन	45639	26936	29941
5	जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच	42763	14461	25194
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण	1486	1377	1380

————————————

तारांकित प्रश्न संख्या 1325

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदयभान सदन में उपस्थित नहीं थे)

To Metal the Unmetalled Passages

***998. Shri Hari Chand Middha :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the following unmetalled passages in the Jind Assembly constitutency :-

(i) Khokhri to Kandela;

(ii) Ital Kalan to Dariyawala via Sangatpura;

(iii) Manoharpur to Lohchab;

(iv) Khunga to Dhatrath; and

(v) Khunga to Raichandwala ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनमें से किसी भी रास्ते को पक्का करने के बारे में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरि चन्द मिढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे जीन्द विधान सभा क्षेत्र में रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मै माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हुए फिर यह पूछना चाहता हूँ कि इन रास्तों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने घुमाकर फिर से वही प्रश्न कर दिया है लेकिन बावजूद इसके मेरे मन में इनके लिए अभी भी सकारात्मकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने खोखरी से कन्डेला के रास्ते को पक्का करने के लिए 4.3.2014 को मना कर दिया था, ईटल कलां से दरियावाला वाया संगतपुरा के रास्ते को पक्का करने से 28.12.2012 को मना कर दिया था, मनोहरपुर से लोहचब तक के रास्ते को पक्का करने से 4.3.2014 को मना कर दिया था। हमारी सरकार के समय में खूंगा से ढाटरथ तक के रास्ते को पक्का करने संबंधी इनकी एक रिक्वैस्ट आई है जिस पर अभी निर्णय करना बाकी है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द बना दिया जायेगा।

श्री हरि चन्द मिढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि आपने मेरे क्षेत्र के सभी रास्तों को बनाने से मना कर दिया है। यदि माननीय मंत्री जी इन रोड्ज को बनाने के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर हां कर देते हैं तो इससे जींद की शान बन जायेगी और ऐसे पुण्य कार्य के लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी रहूंगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जींद जिले में जो रोड बनाने से मना किया गया है, वह हमारी सरकार में नहीं बल्कि पिछली सरकार के समय में किया गया था। हमारी सरकार के समय में तो आपका एक प्रपोजल आया जिस पर मैंने 100 प्रतिशत हां कर दी है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यदि मिढ्ढा जी के जीन्द क्षेत्र की रोड्ज बनाने के लिए हां करते हैं तो मात्र अकेल रास्ते के लिए क्यों हां कर रहे हैं, सरकार उनकी है यदि वे माननीय सदस्य को राहत देना चाहते हैं तो प्रश्न में दिये गये सभी रास्तों को पक्का करना चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मिढा साहब को कहना चाहता हूँ कि वे एक बार फिर से उन सभी रोड्ज, जिनको बनाने से मना कर दिया गया था, उनकी प्रपोजल बनवा कर मेरे पास भेज दें तो निश्चित रूप से इन पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। वैसे मनोहरपुर से लोहचब वाला जो रास्ता है, यह रास्ता चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नाम से है, तो इस रोड को बनाने के लिए तो हम खासतौर से ध्यान रखेंगे।

Bus Stand of Hathin

***1005. Shri Kehar Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that Bus Stand of Hathin town is not functional and there is no bus service in the said Bus Stand; if so, the time by which the said Bus Stand is likely to be made functional togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं; प्रश्न के इस भाग का, इसलिये, सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पिछले दस सालों तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में कईं रूटों पर बस चला करती थी लेकिन पिछले कुछ समय से इन बसों को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र की मांग हैं कि होडल वाया मंडकोला से सोहना, मंडकोला से चंडीगढ़ तथा हथीन से अलवर रूट पर बसें चलाई जायें। हमारा मेवात के साथ लगता क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र के ज्यादातर लोग इलाज के लिए अलवर जाते हैं इसलिए मैं हथीन से अलवर रूट पर ज्यादा बल देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त हथीन-कोंडल, गहलव से कलसाड़ा व पलवल तथा होडल से नूंह जिसकी लम्बाई लगभग 41 किलोमीटर बनती है, के लिए भी बस चलाई जाये। काबिले गौर यह है कि इस रूट पर यात्रियों की बहुत ज्यादा संख्या है। यहां पर मात्र एक बस है और वह भी नूंह डिपो की चलती है। पलवल डिपों की एक भी बस यहां पर नहीं चलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या यहां पर बसों की संख्या बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, हथीन बस स्टैंड का अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। हथीन बस स्टैंड के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि यह बस स्टैंड 19.11.2007 को 39 कनाल 17 मरले के क्षेत्रफल में 73.39 लाख की लागत से बनाया गया था। हथीन बस स्टैंड

1.1.2013 से पहले पलवल-फरीदाबाद डिपो का उप-केन्द्र होता था। जब पलवल अलग हो गया तो हथीन, पलवल डिपो के अधीन आ गया। जहां तक मेरे साथी ने जिक्र किया है कि हथीन बस स्टैंड से बसें नहीं चलती हैं तो इस संबंध में मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय साथी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यहां पर 15 रूट निजी सहकारी परिवहन समितियों को जारी किए गए है तथा 11 रूट्स हरियाणा रोड़वेज के हैं। जहां तक अभी माननीय सदस्य ने बताया कि हथीन से पलवल बस सेवा नहीं है तो इस संबंध में मेरे पास हथीन बस अड्डा से राज्य परिवहन की बस सेवाओं की एक समय सारिणी मौजूद है जिसको मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हथीन से चण्डीगढ़ के लिए फरीदाबाद डिपो की बस 4.20 बजे चलती है, हथीन से पलवल के लिए पलवल डिपो की बस 5.15 बजे चलती है, हथीन से भरतपुर के लिए फरीदाबाद डिपो की बस 5.30 बजे चलती है, उटावड़ से बल्लभगढ़ के लिए फरीदाबाद डिपो की बस 5.50 बजे चलती है, हथीन से बल्लभगढ़ वाया सोहना के लिए फरीदाबाद डिपो की बस 6.00 बजे चलती है, हथीन से पलवल के लिए पलवल डिपो की बस 6.00 बजे चलती है, कोंडल से बल्लभगढ़ के लिए पलवल डिपो की बस 6.15 बजे चलती है, उटावड़ से बल्लभगढ़ के लिए फरीदाबाद डिपो की बस 6.20 बजे चलती है, पिनगुआ से पलवल के लिए पलवल डिपो की बस 6.45 बजे चलती है, उटावड़ से बल्लभगढ़ के लिए पलवल डिपो की बस 6.50 बजे चलती है और बहीन से बल्लभगढ़ के लिए पलवल डिपो की बस 7.00 बजे चलती है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 15 रूटों पर निजी सहकारी परिवहन समिति की बसें चलती है ।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को वर्ष 1993 में 860 निजी सहकारी परिवहन समिति के परमिटों से लगभग 20 करोड़ रूपये सालाना राजस्व के रूप में मिलता था। अब सरकार ने जो नई मंथली परिवहन परमिट स्कीम हरियाणा राज्य परिवहन के लिए बनाई है, इस नई स्कीम के आने से, 860 निजी सहकारी परिवहन समिति के परमिटों से जुड़े 9 हजार परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार पुरानी स्कीम के आधार पर ही इन्हें परमिट प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आप अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसी प्रश्न से संबंधित है । हथीन बस अड्डे से कोई भी बस सेवा नहीं है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जिन बसों का जिक्र किया है, यह पहले से गांवों के रूट हैं । मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा हैं कि गहलव से भमरौला जोगी, कलसाडा वाया भंगूरी पलवल के लिए कोई भी बस सेवा नहीं है । इन गांवों में 10 साल पहले बस चलती थी, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में पूरी तरह से अनदेखी हुई और इन बसों को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन बसां को फिर से चालू किया जाये, क्योंकि हथीन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां पर यातायात के लिए कोई अन्य साधन भी मौजूद नहीं हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पलवल-हथीन-पिनगुआ मार्ग पर दि दुर्गापुर सहकारी परिवहन समिति की बस 7.15 बजे चलती है, दि रानीयाला खुर्द सहकारी परिवहन समिति की बस 7.55 बजे चलती है, दि टीकरी ब्राह्मण सहकारी परिवहन समिति की बस 8.30 बजे चलती है, दि चौहान सहकारी परिवहन समिति की बस 9.00 बजे चलती है, दि मेवात

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

सहकारी परिवहन समिति की बस 10.00 बजे चलती है, दि दुर्गापुर सहकारी परिवहन समिति की बस 11.15 बजे चलती है, दि रानीयाला खुर्द सहकारी परिवहन समिति की बस 12.00 बजे चलती है, दि टीकरी ब्राह्मण सहकारी परिवहन समिति की बस 12.30 बजे चलती है, दि चौहान सहकारी परिवहन समिति की बस 13.00 बजे चलती है, दि मेवात सहकारी परिवहन समिति की बस 14.00 बजे चलती है, दि दुर्गापुर सहकारी परिवहन समिति की बस 15.15 बजे चलती है, दि रानीयाला खुर्द सहकारी परिवहन समिति की बस 16.00 बजे चलती है, दि टीकरी सहकारी परिवहन समिति की बस 16.30 बजे चलती है, दि चौहान सहकारी परिवहन समिति की बस 17.00 बजे चलती है और दि मेवात सहकारी परिवहन समिति की बस 18.00 बजे चलती है। (विघ्न)

श्री केहर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में 4500 बसों का जो बेड़ा है, उससे तो सरकार को घाटा हो रहा है। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि मेरे पास हथीन बस अड्डे के अंदर का फोटो है, जिसमें यार्ड में लगी बसें सवारियों से भरी हुई हैं। माननीय सदस्य का जो निजी सहकारी परिवहन समिति के बारे में सवाल है वह मूल सवाल से हट कर है और यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। कई माननीय सदस्यों के माध्यम से भी निजी सहकारी परिवहन समिति के बारे में प्रेजैंटेशंज आई हैं, उसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डिस्कस करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य श्री केहर सिंह को यह भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 860 नहीं बल्कि 880 निजी सहकारी परिवहन समितियों को परमिट दिये गयें थे। यह परिवहन समितियां इन सभी 880 रूट्ज पर अपनी सेवाएं दे रही थी ।

————————

To Metal unmettalled Passage

***1014. Shri Anoop Dhanak :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Sotha to Kheri Jalab in Uklana constituency; if so, the time by which the said work is likely to be completed togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। इसलिए, समय का प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, गांव सौथा से खेड़ी जालब मण्डी का रास्ता केवल 4-5 किलोमीटर का है लेकिन हमारे किसान भाइयों को वहां तक जाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मुझे 2-3 दिन पहले आश्वस्त किया था कि हम इस रोड़ को बना देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए इस सड़क को बनवाने का कष्ट करें ताकि इन

गांवों के लोगों को 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर न लगाकर महज 4-5 किलोमीटर चलकर ही अनाज मण्डी में जाने की सुविधा सुलभ हो सके।

श्री अध्यक्ष : अनूप जी, आपने अपना रास्ता पक्का करवाने के लिए हामी तो कृषि मंत्री से भरवाई है लेकिन आप सवाल लोक निर्माण मंत्री जी से पूछ रहे हैं। (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप जो बात माननीय सदस्य से कह रहे हैं इस परिपेक्ष्य में मैं चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शहरों के रोड़ पक्के किये जायेंगे और गांवों के रोड्ज को कृषि विभाग के अधीन मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पक्का किया जायेगा। अत: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि हम इनके क्षेत्र की सड़क को बना देंगे।

———————

Construction of Road

***1024. Shri Om Parkash Barwa :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passages from Behal Town to Dhani Kehra, Dham Hatti and Dhani Ramu ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवश्य बताना चाहता हूं कि इनको यह प्रश्न कृषि मंत्री से पूछना चाहिए था क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड कृषि विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और हमारा विभाग 6 करम से कम का रास्ता नहीं बनाता है।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री को बताना चाहूंगा कि इस रास्ते की लम्बाई ही 4 करम की है। वहां के किसान इस रास्ते को 6 करम की बनाने के लिए जमीन देने को भी तैयार हैं। आप चाहें तो उनसे जमीन देने का एफिडेविट भी ले सकते हैं।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस रास्ते के लिए 4 करम की जमीन दिलाते हैं तो इस रास्ते को माननीय कृषि मंत्री जी बनवा देंगे। अगर इस रास्ते के लिए हमें 6 करम की जमीन प्राप्त होती है तो हम इस सड़क की वायबिलिटी चैक करके इस रास्ते को बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय लोक निर्माण मंत्री का इस रास्ते को बनाने संबंधी आश्वासन देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

———————

तारांकित प्रश्न संख्या 1085

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उमेश अग्रवाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

———————

तारांकित प्रश्न संख्या 1091

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

———————

To Enlage the Nullah

***1029. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Urban Local bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enlarge the size of existing nullah between city Park and Mohana road; if so, the details thereof ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान् जी। उक्त कार्य के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 6 फरवरी, 2016 को एक जनसभा में घोषणा की थी कि सिटी पार्क से ऊंचागांव जाने वाली ड्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा । नगर निगम फरीदाबाद द्वारा इस कार्य के लिए व्यावहारिक सर्वेक्षण और टैण्डर इनवाइट कर लिए गए हैं तथा शीघ्र ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके इस काम को शुरू कर दिया जाएगा । उम्मीद है कि 7 दिनों के भीतर ही यह डी.पी.आर. बनकर तैयार हो जाएगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1047

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थी।)

To Open a Degree College in Rania

***1169. Shri Ram Chand Kamboj :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made to open a Degree College in Rania of Distt Sirsa in Rania Assembly constituency on 20th April, 2015; if so, the time by which the construction work of the building and classes are likely to be started in the said college togetherwith the details threof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

श्रीमान् जी, दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है तथापि, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा रानियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिला सिरसा में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा दिनांक 20 जुलाई, 2015 को की गई थी। तदानुसार राज्य सरकार ने रानियां में राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राजकीय महाविद्यालय, रानियां के भवन निर्माण हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग को 8-10 एकड़ भूमि का चयन/उपलब्ध करवाने हेतु उपायुक्त, सिरसा को आग्रह किया गया है। भूमि के उपलब्ध होने के बाद भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी। ऊपरलिखित महाविद्यालय में कक्षाएं आरम्भ करने का मामला विचाराधीन है।

श्री रामचन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस डिग्री कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी तथा इसका भवन निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वहां के जिला उपायुक्त द्वारा हो रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ साथ रामचंद कम्बोज जी भी उसमें सहयोग करें और जैसे ही भूमि अधिग्रहण की प्रकिया पूरी होगी, हम काम शुरू कर देंगे।

श्री रामचंद कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, हमारे रानिया में लड़कियों के लिए गवर्नमैंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल पहले ही चल रहा है। अगर उसमें लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलकर कुछ क्लासिज इस साल शुरू कर दी जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे यहां की लड़कियां 10+2 के बाद शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाती इसलिए लड़कियों के लिए कुछ क्लासिज इसी गवर्नमैंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल में ही शुरू हो जाएं तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरी वहां के प्रिंसिपल और मैनेजमैंट से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि वे इस कॉलेज के लिए कमरे अवेलेबल करवा देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की चिंता वाजिब है परंतु जिस विद्यालय की बात ये कर रहे हैं वहां बच्चों की संख्या पहले ही ज्यादा है। एक बार हम इसकी उचित व्यवस्था करवा लें उसके बाद कॉलेज के लिए क्लासिज प्रारम्भ करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1081

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नगेन्द्र भडाना जी सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

To Ply Volvo Bus

***1089. Shri Tek Chand Sharma :** Will the Transport Minsister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Volvo Bus service from Faridabad to Chandigarh; if so the time by which the abovesaid bus service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी नहीं; प्रश्न के इस भाग का इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है।

टेकचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक के लिए एक वोल्वो बस चलाने का अनुरोध किया था । रिसैंटली सरकार द्वारा फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी की गिनती में लिया गया है। स्मार्ट सिटी की अनाउंसमैंट होने के बाद जहां एक तरफ तो हम वहां सारी सुविधाएं देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वहां से चंडीगढ़ तक वोल्वो बस की सुविधा भी नहीं हो पाएगी तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक वोल्वो बस जरूर चालू की जाए क्योंकि रोजाना हजारों लोग वहां से चंडीगढ़ आते हैं। हमारे फरीदाबाद की तरफ से मूलचंद शर्मा जी, विपुल गोयल जी, नगेन्द्र जी, सीमा त्रिखा जी आदि जितने भी विधायक हैं उनका अनुरोध है कि यह बस सेवा जरूर चालू की जाए। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि हमारे फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक की एक वोल्वो बस जरूर चलाई जानी चाहिए।

श्री कृष्णलाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस समय 39 वोल्वो बसिज हैं जिनमें से 34 बसिज चंडीगढ़-गुड़गांव-जयपुर के लिए चलती हैं। 4 बसिज चंडीगढ़ से जयपुर, चंडीगढ़ से हिसार, गुडंगांव से आगरा और चंडीगढ़ से शिमला रूट्स पर चलती हैं। हमने 26.4.14 को चंडीगढ़ से फरीदाबाद वोल्वो बस चलाई थी लेकिन उसकी एक दिन की रिसीट 28 रूपये 7 पैसे प्रति किलोमीटर आई थी और चंड़ीगढ़ से गुड़गांव की जो बस चलती है उसकी रसीट 63 रूपये 91 पैसे प्रति किलोमीटर आई है। चंडीगढ़ से फरीदाबाद का रन 628 किलोमीटर पड़ता है जबकि चंडीगढ़ से गुडगांव का रन 520 किलोमीटर पड़ता है। 29.4.14 को फरीदाबाद से चंडीगढ़ चलने वाली बस की रिसीट 26 रूपये 56 पैसे आई थी और, उसके बाद यह 42 रूपये 57 पैसे आई थी। एवरेज गुडगांव से चंडीगढ़ चलने वाली बस की रिसीट 58 रूपये 28 पैसे प्रति किलोमीटर पड़ती है। जबकि चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक चलने वाली बस की रिसीट 45 रूपये 57 पैसे आई यानी यह बस घाटे में चल रही है। 45 रूपये प्रति किलोमीटर तो हमारा खर्च आता है। इसके बावजूद भी हमारे साथी और बहन जी कह रही हैं कि यह वोल्वो बस चलनी चाहिए तो हम इसको दोबारा से ट्रायल बेसिज पर चला कर देख लेंगे लेकिन यदि यह बस घाटे में आई तो हम इसको बंद कर देंगे।

श्री टेकचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हो सकता है जानबूझकर उस समय यह बस ओड टाइम में चलाई गई हो। मंत्री जी, यह बात वर्ष 2014 की कर रहे हैं लेकिन अब 2016 चल रहा है यानी दो साल निकल गए हैं। उस समय हो सकता है जानबूझकर फरीदाबाद को पीछे धकेलने का काम किया गया हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सुबह के टाइम दो महीने तक इस बस को चला कर देख लिया जाए। यदि यह बस प्रोफिट में आती है तो इसे चलने दिया जाए अन्यथा इसको बंद कर दिया जाए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि ये हमें इस बस को चलाने का समय लिख कर दे दें हम ट्रायल बेसिज पर फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक की वोल्वो बस चला देंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फिरोजपुर झिरका से मथुरा और आगरा के लिए कोई रोड़वेज की बस चल रही है। यदि नहीं चल रही तो क्या वहां के लिए कोई बस चलाने का प्रावधान है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माध्नध्नीय साथी को बताना चाहूंगा कि इंटर स्टेट बस चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। अगर वहां के लिए हमारे पास परमिट होगा तो इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय साथी इस बारे में मुझे प्रपोजल लिखकर भिजवा दें। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या :1129

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती रेनुका बिशनोई सदन में उपस्थित नहीं थी।)

तारांकित प्रश्न संख्या: 1065

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ दहिया सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Drains

***1152. Shri Pirthi Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a drain to drainout the rainy water which accumulates in the fields of villages Ismailpur, Dablain, Dharamgarh and Sunderpura of Narwana Assembly constituency, if so, the time by which abovesaid proposal is likely to be materialized ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं श्रीमान् जी; इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि गांव इस्माईलपुर, दबलैन, धर्मगढ़, नरवाना तथा सुन्दरपुरा की 800-900 एकड़ जमीन में बरसात का पानी भरा रहता है जिसके कारण वहां के किसान फसल बिजने से वंचित रह जाते हैं। मेरा निवेदन है कि उन गांवों की जमीन में जो बरसात का पानी भरा रहता है उसको निकालने का प्रावधान किया जाये ताकि वहां के किसान फसल की बिजाई कर सकें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि विभाग के पास इस तरह की जानकारी नहीं है कि वहां पर पानी भरे रहने के कारण फसल की बिजाई नहीं होती। यदि ऐसा है तो हम दोबारा से वहां के स्थानीय लोगों से इस बारे जानकारी ले लेंगे। अभी तक इस्माईलपुर, दबलैन, धर्मगढ़, नरवाना तथा सुन्दरपुरा में बरसात से यदि कभी पानी भरता है तो तुरंत उस पानी को पम्पिंग करके सुंदरपुर ड्रेन और नरवाना रजबाहे में डाला जाता है। लम्बे समय से वहां पर पानी भरने की कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है तथा किसी भी तरह से वहां फसल का नुकसान नहीं हुआ है। इस बार भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें भी कहा गया कि उन एरियाज का चयन किया जाये जहां पर लगातार पानी भरा रहता है ताकि जहां-जहां पानी भरा रहता है उसकी निकासी की जा सके, चाहे वे एरियाज शहरी क्षेत्र में हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हों। सरकार ने इससे आगे जाते हुए और भी व्यवस्था की है कि नहर टूटने से जहां पानी भरता है और फसल नहीं हो पाती है तो जिस प्रकार से डिजास्टर मैंनेजमैंट का मुआवजा देते हैं उसी तरह नहर का पानी टूटने से

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

फसल खराब होने पर नहर विभाग को दायित्व ठहरा दिया गया है कि वह मुआवजा देगा। इसके लिए सरकार ने बजट प्रोविजन भी कर दिया है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की ड्रेनों की सफाई का आश्वासन दिया था। अभी बरसात शुरू होने वाली है और जो आश्वासन दिया गया था वह काफी बड़ा आश्वासन दिया गया था। उसके लिए बजट की घोषणा भी की गई थी। यह बात मैं मंत्री जी के नोटिस में भी लाया था। मैं मंत्री जी के नोटिस में फिर लाना चाहता हूं कि उस आश्वासन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मई के महीने के बाद तो बरसात शुरू हो जायेगी। क्या मई तक जो हमारी निजामपुर से रामकली-भरूखेड़ा ड्रेन के निर्माण की घोषणा की गई थी, उसका कार्य हो जायेगा। इसी तरह गतौली से गडवाली-खेड़ाबख्ता-करेला ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाकर निर्माण करना था क्या यह कार्य भी मई तक हो जायेगा ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सारी हांसी ब्रांच की सफाई 19 करोड़ रूपये से की जायेगी। यह बात भी मैं मंत्री जी के नोटिस में लाया था लेकिन अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जहां से हम मुणक नहर के अंदर पानी डालते हैं और अंटा हैड तक पानी लाते हैं । मुणक से 0 से 60 हजार तक जो नहर का सिस्टम बना हुआ है वह कंडम है। अगर उसको ठीक कर दिया जाये पानी चाहे कम हो या ज्यादा हो जो पानी अंटा हैड से भिवानी ब्रांच को, सुन्दर ब्रांच को और हांसी ब्रांच को मिलेगा वह बराबर मिलेगा। क्या इस बारे में भी मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं विधान सभा क्षेत्र वाईज देखता हूं तो सबसे ज्यादा बजटरी प्रोविजन का फायदा मेरे माननीय साथी ढुल साहब ने उठाया है। इन्होंने लगातार सदन में सवाल उठाकर अपने प्रोजैक्ट मंजूर करवाये हैं। जहां तक काम शुरू हाने की बात है तो हम चाहते हैं कि अगली बारिश से पहले पहले काम हो जाये। हम चाहते हैं कि इनके यहां का जो पुल ऊपर उठाना था वह कार्य भी और इनके हल्के की जो ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी थी वह कार्य भी यानी कि इन्होंने जो भी कार्य बताये हैं वे सारे विभाग की प्रपोजल में आ गये हैं और विभाग उन पर जल्द ही कार्य करने जा रहा है। एक ड्रन की सफाई के विषय के बारे में माननीय साथी ने मेरे से बात की थी हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। मेरे माननीय साथी भगवान से प्रार्थना करें कि बरसात अच्छी हो क्योंकि इस बार बरसात कम आई थी। दिसम्बर और जनवरी में जितनी बरसात आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। 50 प्रतिशत कम बरसात हरियाणा में हुई। अभी मार्च में कुछ बरसात हुई है। हम चाहते हैं कि बरसात अच्छी आए। पूरे प्रदेश में हमारे फ्लड कंट्रोल के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हमने समय रहते इस बारे में फरवरी में ही मीटिंग बुला ली थी वरना मीटिंग ही अप्रैल में होती थी जिसके कारण पहले प्रोपर काम नहीं हो पाता था। फल्ड कंट्रोल बोर्ड की हम मई से पहले एक मीटिंग और करेंगे ताकि समीक्षा हो सके कि कितना काम हो गया है। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि इसको लेकर पूरी तेजी से सरकार काम कर रही है ।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 1996 में जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार गई उससे पहले हिसार जिले में बड़ा स्वर्णिम काल था। एक महीने में तीन-तीन या चार-चार

हफ्ते पानी नहरों में मिलता था। उनकी सरकार के बाद जितनी भी सरकारें आई हिसार जिले के साथ बहुत भेदभाव किया गया। इस सरकार के बनने के बाद हिसार के लोगों को उम्मीद थी कि वहां नहरों में उनके हिस्से का पानी मिलेगा। नहरी पानी के लिए नलवा, आदमपुर, बरवाला और हांसी हल्के के लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किए। भाई बराला जी भी वहां गये थे और धनखड़ साहब से भी वहां के लोग मिले थे। उनसे वायदा किया गया कि एक महीने में दो से अढ़ाई हपते उन्हें नहरी पानी दिया जायेगा। आज वहां हालात बद से बद्तर हैं। मेरा मंत्री जी से प्रश्न भी है और रिक्वैस्ट भी है कि क्या यह चुनावी मैनीफैस्टो की तरह सरकार का जुमला ही रहेगा या हिसार जिले के लोगों को पहले की तरह पानी भी मिलेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मान्यवर अध्यक्ष जी, इसमें ईश्वर की कृपा चाहिए। माननीय सदस्य को भी जानकारी है कि पूरे देश में सूखा पड़ा है और हरियाणा में भी मानसून 50 प्रतिशत कम रहा है। इसके अतिरिक्त यमुना में भी हमें जो 3 हजार क्यूसिक पानी साल भर मिलता था वह भी कम होकर एक हजार क्यूसिक के आसपास रह गया है। पहले भी मैंने इसी सदन में इसी सत्र में सूचित किया है कि पहले जहां पूरे हरियाणा में हम चार बार में पानी देते थे उसके लिए हमें 6 हजार क्यूसिक पानी की एक बार में जरूरत होती है। हम हरियाणा को चार हिस्सों में बांटकर एक महीने में 8-8 दिन पानी देते थे। इस बार हमें पानी की कमी होने के कारण हरियाणा को पांच हिस्सों में बांटना पड़ा। क्योंकि 6 हजार क्यूसिक पानी हमारे पास एकत्रित नहीं हो पा रहा था। इस तरह के विशेष संकट से पूरा हरियाणा गुजरा है। काफी मात्रा में हम पानी पहुंचने में सफल रहे लेकिन कुछ इलाकों में हमारे पानी का संकट होने के कारण इतने स्टोरेज नहीं थे जितने समय के लिए हम पानी दे पा रहे थे। पानी की स्टोरेज की व्यवस्था भी उसी बात को ध्यान में रखते हुये बनाई जाती है कि इतने दिन के बाद पानी आ ही जायेगा लेकिन उसका भी संकट आ गया था। यह दौर पूरे हरियाणा के लिए रहा है लेकिन फिर भी हम सिंचाई के माध्यम से गेहूं की अच्छी फसल बचाने में कामयाब रहे हैं । इसी प्रकार से पिछली धान की फसल भी 50 प्रतिशत मानसून होने के बावजूद हम अपने सिंचाई के साधनों से बचा पाये थे। मुझे इस बात की खुशी भी है कि उन फसलों के बचाने के कारण ही हरियाणा को कृषि कर्मण अवार्ड के रूप में 2 करोड़ रूपये की राशि प्रधानमंत्री जी के हाथों मिली है । उस हिसाब से हम धान के उत्पादन में देश में अव्वल रहे हैं। लगभग 13 राज्यों में सूखा रहा है। अब भी प्रार्थना यही है कि अच्छी बारिश हो जाये और यमुना नदी में पानी बढ़ जाये। एस.वाई.एल. नहर की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अगर किसी तरह हमारा पानी बढ़ जाये तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि हम हिसार को पीछे नहीं रहने देंगे लेकिन यह बहुत कुछ नियति पर निर्भर करता है। प्रकृति उस प्रकार से बरसे, इन्द्र देवता की कृपा हो और माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई जी पूजा-पाठ में भी विश्वास करते हैं तो उस नाते से इनसे भी अनुरोध है कि यह बारिश की कृपा करवायें।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1152 जो पूछा गया है उसमें इसमाईलपुर, दबलैन, धर्मगढ़ तथा सुन्दरपुरा गांवों के खेतों में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है उसकी निकासी के लिए ड्रेन के निर्माण बारे पूछा है और माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उस ड्रेन के निर्माण को नकारा है। इसके बारे में मैं ड्रेन के निर्माण की बात के अतिरिक्त यह पूछना चाहता हूँ कि अंडरग्राउंड वॉटर की टेबल को रिचार्जिंग करने के लिए

[श्री सुभाष बराला]

सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वह भी पानी की निकासी से संबंधित है लेकिन वह इससे अलग प्रश्न जरूर है। सिरसा जिले में ऐलनाबाद विधान सभा क्षेत्र में जो नाथूसरी चौपटा है उससे हम चाहे ऐलनाबाद की तरफ जायें या उधर से हम भट्टू की तरफ आयें या भादरा की तरफ जायें यानि उसके चारों तरफ जल भराव की वर्षों पुरानी समस्या है। वहाँ पर उस जल निकासी का या वहाँ पर जल भराव न हो इसकी भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि आज ससुराल पक्ष पर सभी खुश हैं लेकिन पीहर की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरे अपने गांव लाम्बा खेड़ी में ड्रेन पर पुल नहीं है इसलिए उस ड्रेन पर पुल का निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी को बताना चाहता हूँ कि उनकी डिमांड पर भी हम विचार करेंगे। इसी प्रकार से श्री सुभाष बराला जी ने दोनों तरह का सवाल एक साथ किया है। जहाँ पानी कम है वहाँ पर रिचार्जिंग का सवाल है और जहाँ ज्यादा है वहाँ पर पानी निकासी का भी सवाल है। हमने अपनी सारी ड्रेनों का डिजाइन हब बना-बना कर इस प्रकार से बनाया है ताकि वे रिचार्जिंग का हिस्सा बन सकें और नहर नहीं है तो किसान उससे सिंचाई भी कर सकें। उसमें डेढ़-दो फुट के बाद पानी को रोक कर ऐसा सिस्टम किया गया है जिससे वे रिचार्जिंग का माध्यम बनें, अपनी सभी ड्रेन्स को इस रूप में डिजाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार डार्क जोन के बारे में डॉ0 अभय सिंह यादव जी बार-बार सवाल उठाते रहते हैं उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ टेल्स हैं वहाँ पर हम 390 इंजैक्शन बोर लगा रहे हैं ताकि जिस भी सप्ताह में बारिश आ जाये और हमें पानी की जरूरत न हो तो हम इन इन्जैक्शन बोर के माध्यम से पानी को जमीन के अन्दर डाल दें। इस बारे में हमारी तीसरी योजना है कि गांवों से दूर बने जोहड़ जो पहले से ही वेस्ट वॉटर से भरे हुये नहीं हैं और जो पशुओं को पानी पिलाने के लिए गांवों से दूर होते थे, उनको भी हमने रिचार्जिंग का माध्यम बनाया है। जो जोहड़ ज्यादा भरे हुये हैं उनको हमने ड्रेनों के साथ जोड़ कर पानी निकालने के लिए और जो जोहड़ ज्यादा भरे हुये नहीं हैं उनको रिचार्जिंग के लिए उपयोग किया जायेगा। पहले 2800 जोहड़ थे लेकिन अब हमने 1450 जोहडों की और लिस्ट बनाई है ताकि जब भी हमारे पास नहरों में सरप्लस पानी हो तो पहले उन जोहड़ों को भरें ताकि उससे हमारा पानी और ज्यादा मात्रा में रिचार्ज हो। जहाँ पर सेलेनिटी ज्यादा है, जहाँ पर ज्यादातर पानी भरा रहता है तथा जमीनें खराब हो गई हैं उन जगहों को चिह्नित करके वहाँ जमीनों को सुधारने के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है। निश्चित रूप से नाथूसरी चौपटा के आस पास का ईलाका मैंने भी देखा है इसके अतिरिक्त जैसाकि अभी कहा गया था कि ससुराल पक्ष का होने के कारण नाथूसरी चौपटा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसी परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि जैसाकि आज बजट पेश होगा और माननीय वित्त मंत्री जी पिटारे खोलेंगे और यदि इस पिटारे में से इरीगेशन विभाग के लिए कोई अच्छी खुशखबरी सामने आती है तो निश्चित रुप से नाथूसरी चौपटा को प्रायॅरिटी पर रखकर वहां के काम किए जायेंगे।

To Improve Women Education

***1281. Shri Jasbir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state the steps taken by the Government to improve the women education in the State ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री जसबीर देशवाल जी ने पूछा है कि महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गये हैं। स्पीकर सर, हिन्दुस्तान बेटियों का देश है और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' का कार्यक्रम 22 जनवरी को माननीय प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र भाई मोदी ने पानीपत से शुरु किया था। अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये हैं-

1. राज्य में 41 नये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय खोलने प्रस्तावित हैं जिनमें 34 विद्यालय मेवात, 2 विद्यालय मोरनी हिल्स, 1 विद्यालय जैनाबाद, 1 विद्यालय ढोकिया (रेवाड़ी), 1 विद्यालय भिवानी शहर, 1 विद्यालय सोनीपत शहर और 1 महिला सैनिक विद्यालय खुड़ान(महेन्द्रगढ़) सम्मिलित हैं।
2. शिक्षा के क्षेत्र में पिछले खण्डों में 32 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों एवं 36 कन्या छात्रावासों की स्थापना की जा रही है।
3. 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं' कार्यक्रम के अन्तर्गत 5268 राजकीय विद्यालयों में 'बालिका मंच' की स्थापना कर दी गई है।
4. विद्यालयों से बाहर बच्चों, विशेषतया लड़कियों को चिन्हित करने के लिए एन.सी.सी. एन.एस.एस. स्काउट एवं गाइड में पंजीकृत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया।
5. सभी राजकीय विद्यालयों में 'बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, 'मेरा पहला गणतंत्र दिवस' एवं 'कन्या जन्मोत्सव' कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। अध्यक्ष महोदय, अब बेटी पैदा होने पर कुंआ पूजन का और उसके लिए राजकीय प्रोत्साहन का कार्यक्रम भी शुरु किया है।
6. 1536 विद्यालयों में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ रही छात्राओं को 'आत्मरक्षा प्रशिक्षण' दिया जा रहा है।
7. बालिकाओं के लिए 6 राजकीय महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 6 राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात है वह कहां-कहां खोले जाएंगे क्योंकि इसमें हमने एक हमारे क्षेत्र के लिए भी मांगा था। जीन्द से सफीदों तक 40 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो मंत्री जी ने और सरकार ने भी एक दिन सदन में अनाऊंस किया था कि हर 20 किलोमीटर पर लड़कियों के लिए एक महाविद्यालय खोला जाएगा। मेरा जामनी गांव है जो पिल्लुखेड़ा और जीन्द के बीच में पड़ता है। क्या इस कस्बे में भी लड़कियों के लिए कोई महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव है। मैंने पहले भी इसकी मांग रखी है

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री जसबीर देशवाल जी के द्वारा जो जामनी और पिल्लू खेड़ा में लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है तो इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो

[श्री राम बिलास शर्मा]

घोषणायें की गई है उन घोषणाओं में प्रदेश के शिक्षा संस्थानों की झलक निम्न प्रकार है। राज्य में वर्तमान में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए 1043 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 269 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 189 राजकीय उच्च विद्यालय एवं 297 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ 90387 सह-शिक्षा राजकीय विद्यालय उपलब्ध हैं। राज्य में 41 नये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत 60-40 रेशो के सांझा कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। जहां तक पिल्लुखेड़ा में महिला कालेज की खोलने की बात है तो मैं उस परिपेक्ष्य में माननीय सदस्य श्री जसबीर सिंह देशवाल जी को बताना चाहूँगा कि इस बार 11 नये कालेजिज खोलने पर विचार किया जा रहा है। आज विधायक लतिका शर्मा जी का जन्मदिन है तो कल जो इनके विधान सभा क्षेत्र रायपुररानी में एक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी वह इनके जन्म दिन का तोहफा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) इसी प्रकार से जब पिछली बार चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी स्पीकर गैलेरी में विराजमान थे और माननीय विधायक श्रीमती प्रेम लता जी सदन में उपस्थित थी तो उस दिन चौधरी विरेन्द्र सिंह जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर 'अलेवा' में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। (शोर एवं व्ययवधान)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अब यदि किसी का जन्मदिन ही न आवे तो यह तो बड़ी चिंता की बात है। (हंसी) इस तरह तो हमारे क्षेत्र में कभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे ही नहीं। (हंसी व व्यवधान) हमें तो अपना जन्मदिन ही याद नहीं।(हंसी व व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब को ही नहीं हम जैसे कई लोंगों को भी पता नहीं है कि हमारा जन्म कब हुआ था। (हंसी)

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मैंने अपने क्षेत्र के पांच-छह स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए माननीय मंत्री के पास लिखकर भेजा हुआ है। ये स्कूल गांव खेड़ा खेमावती, गांगुली, बाखेड़ा तथा बुढ्डा खेड़ा में स्थित है। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में करसिंधू स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ था, अगर इस स्कूल का सैशन इसी सत्र में शुरू हो जाये और स्टॉफ का भी प्रबन्ध कर दिया जाये तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब जब बात करसिंधू गांव की आई है तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि करसिंधू को लेकर कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। पिछले सैशन में मैंने करसिंधू स्टेशन तक एक सड़क की डिमांड रख दी थी तो उसका जवाब यह आया कि करसिंधू में किसी तरह का कोई स्टेशन मौजूद ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक करसिंधू गांव उचाना क्षेत्र के अधीन आता है मेरा निवेदन है कि मेरी डिमांड को उचाना क्षेत्र के करसिंधू गांव में कार्यान्वित न कर दिया जाये। (शोर एवं हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री जसबीर देशवाल जी ने लड़कियों के महाविद्यालय के संबंध में भी जानकारी मांगी है, उसका जवाब दे दिया गया है। अब इन्होंने करसिंधू गांव के स्कूल की अपग्रेडेशन के बारे में बताया है और कहा है कि इस अपग्रेड हुए स्कूल को इसी सत्र से आरम्भ कर दिया जाये तथा स्टॉफ का प्रबन्ध भी कर दिया जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के समय में बिना फाईनेंशियल एप्रूवल के ही 93 विद्यालयों को अपग्रेड करके उसकी लिस्ट कंसंर्ड क्षेत्रों में दे दी

गई थी। यह बात बिल्कुल साफ है कि जब किसी विद्यालय को अपग्रेड किया जाता है तो उसके लिए अलग से अध्यापकों की पोस्ट सैंग्शन करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए साईंस टीचर की पोस्ट अलग से, एस.एस.टी. टीचर की अलग से, टी.जी.टी. तथा पी.जी.टी की अलग से पोस्ट्स को सैंग्शन किया जाता है। जहां तक बात विधायक जसबीर सिंह देशवाल जी के प्रश्न की है तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि करसिंधू गांव के स्कूल को इस बार पूरे विधि-विधान से चालू किया जायेगा।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" अभियान के तहत अनेक जगहों पर कॉलेज व स्कूल खोलने की बात कही है लेकिन इसके बावजूद मेरे इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरे अपने गांव गंगवा में जिसके साथ आजादनगर का भी काफी क्षेत्र लगता है, वहां पर पिछले साल लड़कियों के आंठवी क्लास तक के स्कूल को 12वीं क्लॉस तक अपग्रेड करते हुए प्रिसिंपल को भी लगा दिया गया था लेकिन उस स्कूल में टीचर्ज को पोस्टिड नहीं किया गया और फलस्वरूप अब यह स्कूल फिर से आंठवी तक का ही रह गया। तीन चार महीने तक प्रिंसिपल भी वहाँ पोस्टिड रहा, बच्चे भी आये लेकिन जब स्टॉफ को नियुक्त नहीं किया गया तो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस स्कूल को दोबारा से 8वीं क्लास से 12 वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम किया जायेगा तथा स्टॉफ नियुक्त किया जायेगा। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के भूरा गांव में आठवीं कक्षा तक का स्कूल है, भवन पूरा बना हुआ है अत: मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्कूल को भी 10वीं कक्षा तक अपग्रेड किया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर गंगवा का नलवा हल्के में गंगवा गांव है और ये भी बेचारे पिछली सरकार के मारे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि गंगवा स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने में सहयोग करें । हम निश्चित रूप से इस नये शैक्षणिक सत्र में स्कूल को अपग्रेड भी करेंगे और स्टॉफ की जो कमी है उसे भी पूरा करेंगे।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, राजकीय स्कूल गंगवा में बच्चों की संख्या जितनी है, उतनी किसी भी स्कूल में नहीं है । स्कूल में दाखिला भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। आजाद नगर का बहुत बड़ा एरिया साथ लगने के कारण लड़कियां भी दाखिला लेने के लिए तैयार हैं, मगर दाखिला नहीं हो पा रहा है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्कूल में बच्चों की संख्या के साथ-साथ स्कूल का भवन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, इसके लिए हम मदद करेंगे।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मैंने 7-8 महीने पहले राजकीय स्कूल, बिठमड़ा को अपग्रेड करने की बात कही थी। यह स्कूल अपनी बिल्डिंग व कमरे आदि के सभी नॉर्म्स पूरे करता है, लेकिन फिर भी इस स्कूल को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी बहन श्रीमती प्रेमलता जी को बताना चाहता हूँ कि इस नये शैक्षणिक सत्र में इस स्कूल को अपग्रेड किया जाना विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दो समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक समस्या तो यह है कि हमारे समालखा में कोई भी लड़कियों का राजकीय स्कूल नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है। (हंसी)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आज ही के दिन जन्म दिन माना जाये। (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सदन में रवीन्द्र कुमार सबसे युवा और आकर्षक विधायक हैं। हम दोनों गांव से संबंध रखते हैं। जब मैं वर्ष 1982 में विधायक था, गांव के किसी विद्वान ने अपनी माँ से पूछा था कि मेरा जन्म दिन कब है? माँ ने कहा कि उन दिनों में बारिश ज्यादा हुई थी और बाजरा भी घना हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा बारिश के कारण बालू रेत में हमेशा बाजरा ज्यादा होता ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहता हूँ कि जन्मदिन की कोई बात नहीं है, हम समालखा में लड़कियों के लिए स्कूल जरूर बनवायेंगे।

Requirement of Potable Water

***1175. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the current states of potable water being supplied in Julana Town togetherwith the requirement thereof ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : श्रीमान जी, जुलाना कस्बे में 32.60 लाख लीटर की आवश्यकता के विरुद्ध लगभग 27.50 लाख लीटर पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैंने 16 तारीख को भी पीने के पानी के बारे में सवाल पूछा था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जुलाना हल्के के लिए तमाम वॉटर कैनाल और अन्य स्कीमों की विधिपूर्वक जांच करवायेंगे। क्या माननीय मंत्री जी हाउस में यह इंश्योर करेंगे कि उन्होंने जांच कमेटी बना दी है ? मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जुलाना के निवासियों को 27.50 लाख लीटर पानी दिया जा रहा है। आज भी अगर आप हाउस की कमेटी बना दो और वह जुलाना में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां पर 5-5 दिन में एक बार पानी आता है। जुलाना में विभाग ने 31 करोड़ रूपये खर्च करके स्कीम बनाई है फिर भी वहां पीने योग्य पानी नहीं पहुंच रहा है। इस पानी की अगर जांच करवाई जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह पानी वास्तव में पीने योग्य नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जुलाना में कुल 72 गांव हैं जबकि केवल 5 गांवों को छोड़कर एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। विभाग ने जो करोड़ों रूपया लगाया है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को जैसा कि पहले भी बता दिया था कि हम इनके कस्बे में पानी के लिए विजिलैंस इन्कवायरी करवाएंगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि ये मुझे अपनी समस्या लिखित रूप में दे दें मैं इस समस्या की पूरी जांच करवाऊंगा।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंनें माननीय मंत्री जी को पहले ही सारी समस्या लिखकर दी हुई हैं। अब दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है।

Rehabilitation of the Colonies

***1316. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether it is a fact that funds for the rehabilitation of the residents of Rajiv Colony, Indra Colony, madrasi colony and Mata Mansa Devi colony have been deposited by HUDA in the year 1996 and 2008, but no steps have been taken so for the rehabilitation; and

(b) if so, the time by which the residents of above said slum dwellers/ colonies are likely to be rehabilitated togetherwith the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) राजीव कालोनी, इन्दिरा कालोनी और मद्रासी कालोनी के निवासियों द्वारा वर्ष 1996 और 2010 में उनके पुनर्वास के लिए जमा की गई राशि इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष	जमा राशि (र)
1	राजीव/इन्दिरा कालोनी	2802	1996	32,35,000/-
2	राजीव/इन्दिरा कालोनी	875	2010	76,75,500/-
3	मद्रासी कालोनी	282	2010	25,86,000/-

पुनर्वास के लिए माता मनसा देवी कालोनी के झुग्गीवासियों के द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं की गई।

(ख) राजीव कालोनी व इन्दिरा कालोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिये पहले चरण में बुढ़नपुर गांव के निकट 4.75 एकड़ क्षेत्रफल में 512 फ्लैटों के निर्माण के लिये 37.20 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का आकलन बनाया गया है, जोकि मंजूरी के लिए प्रक्रिया में है। फ्लैटों के आबटन की तारीख से तीन साल के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है। बाकी बचे चिन्हित झुग्गीवासियों के पुनर्वास का कार्य, उसी भूमि पर चरणों में किया जाएगा जहाँ वो वर्तमान में रह रहे हैं।

जहाँ तक मद्रासी कालोनी के झुग्गी वासियों के पुनर्वास का प्रश्न है, इसके लिये लगभग 1.76 एकड़ भूमि, सैक्टर 20 पंचकूला में चिन्हित की गई है। माता मनसा देवी कालोनी के झुग्गी वासियों के पुनर्वास की योजना, योग्य व्यक्तियों की पहचान के बाद बनाई जायेगी।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 30 साल से इन कॉलोनीज़ के गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

जा रहा है। हर बार जब इलैक्शन आते हैं तो इन्हें फॉर्म बांट दिए जाते हैं और फिर उनसे पैसे जमा करवा लिए जाते हैं लेकिन पुनर्वास के नाम पर वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई 15.00 बजे गई है। मद्रासी कालोनी, इंदिरा कालोनी और राजीव कालोनी लगभग वर्ष 1980 से वहां स्थापित हैं । 35 साल हो गए हैं लेकिन वहां अभी तक एक भी मकान नहीं बना है । मंत्री जी, आपने कहा है कि 512 फ्लैटस के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया एक साल से शुरू है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में भी इस बारे प्रश्न लगाया था कि 1996 में जो यह योजना बनी थी उसको इम्पलीमैंट क्यों नहीं किया गया इसलिए इस बारे कोई न कोई जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव है कि मुम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार पुनर्वास के लिए पी.पी.पी. मोड पर मकान बनाए जाते हैं, ई.डब्ल्यू.एस.हाउसिज बनाए जाते हैं, मैं समझता हूं कि अगर उसी तरह हमारे यहां भी पी.पी.पी. मोड की प्रकिया को एडॉप्ट करेंगे तभी ये मकान बन सकते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने चितां व्यक्त की है कि चुनाव आते हैं तो लोगों से इस प्रकार की दरखास्तें लेकर उनको धोखा देने की प्रवृति रही है। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2010 तक इस प्रकार की प्रक्रिया कहीं न कहीं इस बात की तरफ निश्चित तौर पर संकेत करती है कि जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो सुझाव दिया है कि पी.पी.पी. मोड पर इस प्रकार की स्लम बस्तियों का निर्माण करके पुनर्वास की व्यवस्था करवाई जाए। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का भी संकल्प है कि हमें हरियाणा को स्लम-फ्री करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि आपके सुझाव पर विभाग निश्चित तौर पर विचार करके इस पर कारवाई करेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

अतांरांकित प्रश्न एवं उत्तर

Jag Mag Gaon Yojna

286. Shri Nagender Bhadana
Shri Naseem Ahmed } **:** Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) the name of the village in which power is being supplied under 'Jag Mag Gaon Yojna 'from October, 2014 till to date togetherwith the number of hours the electricity is being supplied to these villages; and

(b) Whether the electricity Bills are being deposited by the consumers of these villages regularly; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) "म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के अन्तर्गत जहां बिजली सप्लाई 12 से 15 घंटे तथा 15 से 18 घंटे तक बढ़ा दी गई है उन गांवों के नाम निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं.	सर्कल का नाम	फीडर का नाम	गांवों की संख्या	गांवों के नाम
उ.ह.बि.वि.नि.				
		कामबस्सी	5	कामबस्सी, कामबास, कम्बोमाजरी, अकालगढ़ तोलावाली
		डेल्लूमाजरा	6	डेल्लूमाजरा, नन्योला, खुरचनपुर, लोटान, बटरोहां एवं पंजौला
		ब्राह्मण माजरा	6	खुड्डा खुर्द, सलारहेड़ी, करधन, ब्राहमण माजरा, नग्गल एवं खोजकीपुर
		रौलो	5	रौलो, मुन्नरहेड़ी, शारसहेड़ी, चांदपुरा एवं रामपुर
		काम्मी	9	सुल्तानपुर, काम्मी, सुंदरपुर, जलौली, नगल, अलीपुर टॉऊन, टोका, शामतू एवं रात्तेवाली
		रिहोड़	5	रिहोड़, खटौली, सुखदर्शनपुर, बटवल एवं तंडारडू
		फिरोजपुर	12	गढ़ी-कोटाहा,सुल्तानपुर, रेहना, मसूमपुर, देबर, गनौली, डन्डरौली, फिरोजपुर, पीरेवाला, भागपुर, रतौड़ एवं भौली
		खेतपुराली	34	मानक टाबरा, अमराला, रूड़की, कजामपुर, जयंतीपुर, पिंजावाली, मुराद नगर, बहरोली, रामपुर, भुल्ला खेड़ी, थाड़ियों, रत्ती,गणेशपुर, दुल्लोपुर, खेतपुराली, दुधगढ़, डडवाली, लेद सबीलपुर, टिब्ब बलौटी, बुंग्गा, बेलवाली एवं आसरेवाली
1	अम्बाला	दुबली	3	दुबली, खानपुर, लांडा
		अलावपुर	6	रामपुर, छप्पड़ा, अलावपुर, हामिदपुर,हरड़ी
		हरियोली	5	नगला, हरियोली, नरायणगढ़ माजरा, पसीयाला
		मंसूरपुर	5	मोहरा, मंसूरपुर, साहिबपुरा, भूरामाजरा, दूरनां
		तंडवाली	4	तंडवाली, सोहाता, खानपुरा, रावमाजरा
		गगनपुर	9	सिमबिया, बुडियां, होली, रूकड़ी, गगनपुर, कूलपुर, दोसड़का, सिसरगढ़ एवं तंगाली
		अहेमा	2	अहेमा, बाहरी

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
		मोहड़ी	2	मोहड़ी एवं भान्नोखेड़ी
		मेहला	3	सोंटा, सोंटी, मेहला
		बिशनगढ़	4	बिशनगढ़, सेगटा, सेगटी, नग्गल
		तेजां	9	मथेड़ी, हिमांयूपुर,खासपुर, सकराओं, मुजफरा, चोरमस्तपुर, पठानमाजरा, तेजां, गोबिन्दगढ़
		कंजाला	6	कंजाला, नेकनावा, छंसौली, फिरोजपुर, तपड़ियां-आर, लालपुर
		मिर्जापुर	9	मिर्जापुर का माजरा, बरखेड़ी, बरखेड़ी का माजरा, खानपुर लभाना, ओखल, लखनौरा, अंधेड़ी, नंगला राजपुताना
		ककड़ माजरा	6	बापोली, कलाल माजरी, भैरों, बिचपड़ी, चट्टा, ककड़ माजरा
		ककराली	14	ककराली, बागवाला, बागवाली, गोलपुरा, ठरवा, समानवा, हंगोला, हंगोली, सरकपुर, टाबर, बजीदपुर, बेहवलपुर, मौली, हरीपुर
		संगराना	5	भगवानपुर, नायागांव, भरौली, खेड़ा गन्नी, संगराना
		नारायणपुर	9	शाहपुर, नारायणपुर, डकरा, बधोड, मंदापा, मीरपुर, रत्ता टिब्बी, गोबिनपुर, तराकवाला
		बरौना	8	बरौना खुर्द, टिब्बी माजरा, बरौना कलां, खेड़ी, हरीपुर, समलेहड़ी, शाजनपुर
		दरयापुर	5	दरयापुर, लंगरपुर, देवरखाना, लोहट एवं मुण्डा खेड़ा
		खातीवास	2	खातीवास एवं धौड
		मातन हेल	1	मातन हेल
		बाकरा	1	बाकरा
2	झज्जर	मलिकपुर	2	आजाद नगर, छूछकवास
		मछरौली	3	मछरौली, काहडी भठेरा, घटौली
		डावला	4	डावला, खाजपुर, बाबरा, रणखंड़ा
		तलाव	2	तलाव, खेड़ी खुमार

1	2	3	4	5
		बुपनियां	2	बुपनियां, शाहपुर
		कसार	2	कसार, सराय
		गामड़ी	3	रसूलपुर, गामड़ी डेरा एवं कवारतन
		ब्राह्मणीवाला	2	ब्राह्मणीवाला, नरवालगढ़
		टीक	1	टीक
		मुंदेरी	1	मुंदेरी
		लेंडर कीमा	1	लेंडर कीमा
3	कैथल	देयोरा	1	देयोरा
		मंझहेडी	3	मगेंरा, मंझहेडी, मुल्लापुर
		गढ़ी साहिब	5	महमुद पुर, मलिक पुर, अजीम गढ़, गढ़ी नाजीर, सादीपुर
		हरनौला	2	सोथा, हरनौला
		चंदलाना	1	चंदलाना
4	करनाल	जलमाना	1	जलमाना
		बयाना	1	बयाना
		सतौंडी	1	सतौंडी
		कलामपुरा	2	पुन्डरक एवं कलामपुरा
		ललयानी	4	ललयानी, जोगी माजरा, सेखांपुर एवं चोपड़ी
		यूनीसपुर-II	3	यूनीसपुर, अरजाहेड़ी एवं मनछूरी
		बजीदा	4	बजीदा, भूसली, डाहा, कम्बोपुरा
		जी.आर.	3	रणवर, गंजोगराही पीपलवाली डोमेस्टिक
		पुराना	3	दनियालपुर, तपराना, नेवल खुर्द
		सरफाबाद माजरा		
		झिनवरहेड़ी	1	झिनवरहेड़ी
		मुरादगढ़	6	इन्द्रगढ़, मुरादगढ़ गढ़पुरखालसा, मनाहरपुर, फाजिलपुर, जौहर माजरा कलां
		रम्भा	1	रम्भा
		तखाना	1	तखाना

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
		पनौरी	2	पनौरी, जमालपुर
		जुंडला	1	जुंडला
		कुटाना	3	कुटाना, बेगमपुर, डडलाना
5	कुरुक्षेत्र	दयालपुर	6	दयालपुर, आलमपुर, समसीपुर, सलारपुर, के ब्रह्ममणा एवं के. राम नगर
		नलवी-2	7	नई बस्ती नलवी, गोली पुरा, सुलाखनी, बोकर माजरा, नाहर माजरा, नलवी एवं राई माजरा
		गुहान	2	गुहान, भेयानी
		जुरासी कलां	4	बोधनी, बोड़ा, जूरासी खुर्द एवं जूरासी कलां
		चिब्बा	4	चिब्बा, उदारसी, हंसाला, झिवरहेड़ी
		किरमीच पुराना आर.डी.एस.	3	सुहेड़ी, इश्कपुर, कावर खेड़ी
		घूमरखेड़ी	3	घूमरखेड़ी, सिंगपुरा, मलिकपुरा
		गिरधरपुरा	5	गिरधर पुरा, लोहारा, खेड़की, रूड़की, जल्लालूदीन माजरा
		खेड़ी-II	2	गुमथला घडू, खेड़ी शिगढ़
		तियोड़ी	4	सरीफगढ़, बकाना, तियोड़ा, तियोड़ी
		चोरपुर	2	मोहड़ी, संभालखी
6	पानीपत	कवी	1	कवी
		नई जाटल	2	जाटल, बिनझोल एवं सौंधापुर
		पसीना कलां	1	पसीना कलां
		किवाना आर. डी.एस.	1	किवाना
		रकसेडा आर. डी.एस.	5	बसेरा, बुढनपुर, कारकोली, रकसेडा, सिम्बलगढ़
		मोहाली आर. डी.एस.	1	राजाखेड़ी
		ब्राह्मण माजरा	1	ब्राह्मण माजरा
		बुडशाम आर. डी.एस.	4	बुडशाम, हरटारी, डिडवाडी, वजीरपुर वजीरपुर टिटाना

1	2	3	4	5
		ऊंटला आर. डी.एस.	1	ऊंटला
		नंगल खेड़ी आर.डी.एस.	1	नंगल खेड़ी
7	रोहतक	बरौना	2	बरौना एवं रोहना
		निलोठी	2	निलोठी एवं खुरमपुर
		रिठाल	2	रिठाल एवं काहनी
		निन्दाना	1	निन्दाना
		गरनावठी	1	गरनावठी
		लाहली	3	लाहली, मुरादपुर, टेकना
		आवँल (प्रस्तावित)	1	आवँल
		बेंसी	3	बेंसी, खरक, गुग्गाहेड़ी
		कंसाला	2	कंसाला, मोरखेड़ी
		मुंगान	2	मुंगान, आसन
		जीन्दरान	1	जीन्दरान
8	सोनीपत	प्रीतमपुरा	3	प्रीतमपुरा, रसोई एवं नाथुपुरा
		मलछा	2	हरसाना मलछा, एवं हरसाना खुर्द
		छिछडाना	3	छिछडाना, मदीना एवं एम.पी. खेड़ी
		टेहा	2	टेहा एवं बरही
		सरगथल	1	सरगथल
		जगदीशपुर	3	जगदीशपुर, टांडा, झुंडपुर
		गढ़ी	4	मिमारपुर, गढ़ी, रसूलपुर, गियासपुर
		बिलांदपुर	2	खेड़ी गुज्जर, बिलान्दपुर
		अहीरमाजरा (पुराना बिलांदपुर)	1	अहीरमाजरा
		रोलद	5	पिनाना, दोदवा, रोलद, बोहला, एस. माजरा
9	यमुनानगर	मन्देबड़ी	9	रतौली, कंसली, खेड़ीरांगरां, फुसगढ़,मन्देबडी, पंजेटो का माजरा, सुधाल, मेहरामपुर एवं गलोली

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
		पंजुपरू	9	खाजूरी, भादुरपुर, जयपुर, खुरड़ी सभा पुर, सुखपुरा, खांडवा, हरीपुर कम्बोज एवं गुलाब गढ़
		मिल्क सुखी	2	मंधार एवं मिल्क सुखी
		ताहरपुर	5	हैदरपुर, ताहरपुर, ताहरी, जेतपुर एवं हिन्दुओं वाला
		नगला	6	बेहलोली, नगला, देहरी, भारोग, छज्जुर माजरा एवं नसरौली
		रतनगढ़	9	रतनगढ़, घौरांग, एम.टी. दामला, किशनपुरा, दामला, कम्बोज माजरी दामला, सैनी माजरा दामला, कुंजाल, दुधला, हरिजन माजरी दामला
		टेही बी	5	गोलनी, सियालवा, प्रीत नगर, टेही, हस्सनपुरा
		मनका	8	मग्गारपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, खान अहमदपुर, भगवानपुर, मणका, मणकी, काशीपुर
		जमाल माजरा	4	धीन, जमाल माजरा, पौंटी, सलापुर
		दौलतपुर	4	ऊंचा चंदाना, दौलतपुर, फरीदपुर, सराहा
		सिलीखुर्द	2	नग्गल, ढोली
		ममाहीलवाली	5	ममाहीलवाली, अरीपुर जटां, झिवरेड़ी, भटौली, भोले का माजरा
		मुसीम्बल	5	कथवाला, छज्जू नगला, तीन का माजरा, शाह कमीशपुर, मूसीम्बल
		कोट	9	सलीमपुर खादड़, टीहानों, लोपान, हरोली, दादुपुर
		आहलुवाला	4	मुकारबपुर, माणकपुर, मडुवाला, गढ़ी बंजारा
		जठेरी	4	जठेरी, लेडा खास, गनौला, फेरूवाला
		सुल्तानपुर	10	अम्बवाला, कपाल मोचन, मिल्क खास, कोटड़ा, अहरवाला, संध्या, उधम गढ़, भवनौली, मुजाफत, अरियावाला
		रसूलपुर	19	कप्तान माजरी, मंगत माजरा, गढ़हौली माजरा, चीमल माजरा, फेरीपुर, सेदुपुर, टिबरी, रामपुर, लहरपुर, दुम्मवाला, निजामपुर, गलौरी, राजपुर,

1	2	3	4	5
				रथाली, असगारपुर, झांड़ा, काला अम्ब कॉलोनी, उधमगढ़
		झांडा	16	यासीन माजरी, फिरोजपुर, बकाला, हवेली, सदीकपुर खंडारा, सुल्तानपुर, कल्याणपुर, बाना बहादुरपुर, रसूलपुर, मिल्क जुब्लियां, सेलहपुर, थ्सका, जाफरपुर जाफरी, रम्मूवाला, महमदपुर, मजूरमाजरा
		कुल	514	
डी.एच.बी.वी.एन.				
1	फरीदाबाद	तिगांव	2	तिगांव, सदपुरा
		फतेहपुर	1	फतेहपुर
		शाहपुर	4	फतेहपुर, ककरीपुर, लाढोली, शाहपुर
		सोताई	1	सोताई
		बड़ोली	3	बड़ोली, भटोला, पहलादपुर
		अटाली	3	अटाली, मौजपुर, घरखेड़ा
		डडसिया	6	भोपानी, पलवली, टीकावाली, रिवाजपुर, बादशाहपुर, देहा
		सोफता	7	सोफता, नंगला जोगियां, शाहपुर खुर्द, मोहल्ला, हरपेहला सीकरी एवं केल्ली
		खोरी	4	खोरी, जाखोपुर, बिजोपुर, सिरोही
2	पलवल	भोंड़	8	भोंड़ सिधरावत, ढडोली, हसनपुर बिलोंदा, नंगल, पतखोड़ी, चेनपुरी एवं कुबडास
		जमालगढ़	4	लाहरवाडी, सिंगालहड़ी, सिहड़ी एवं जेमात
		जैनपुर	10	घरौट, सोमिका, घिगड़का, जनाचौली, खोकियका, अलूका, पुथरी, बिचपड़ी, सपानकी एवं जैनपुर
		लिखी डी. एस.	6	लिखी, खाम्बी, डराना, घसेड़ा, बच्चीपुर एवं अलावड
		अदवर डी.एस.	16	नोसेरा, केराका, गोलपुरी, भरानगाका, अंधाका, सुड़का, मछरौली, बैंसी, जोगीपुर, अडबर, तेंन, बाबुपुर, हुसैनपुर, धनडूका, तैराकपुर एवं सतपुतियाका

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
		किथवाड़ी डी.एस.	8	डकोरा, होसंगाबाद, खेड़ला, लोहा गढ़, मैसा, रसूलपुर, रोनीजा एवं सिहोल
		राम नगर डी.एस.	7	सोहना की ढ़ाणी, महमदपुर, रामनगर, रायसीना, सेप की नगली, हरिया हीरा एवं धुनेला
		11 केवी घघोट डी.एस.	6	कटेसरा, बधराम, सदारपुर, गोपीखेड़ा, घघोट, कुराड़ा
		11 केवी (नए निर्मित) फिरोजपुर डी.एस.	3	अगवांपुर, अल्लाहपुर, फिरोजपुर
		11 केवी बहीन डी.एस.	3	सौंध, लोहीना, सुदंर नगर
		11 केवी भेनडोली डी.एस.	4	भेनडोली, रामगढ़, महोली, भिडूकी
		11 केवी कोंडल डी.एस.	2	कोंडल, मानपुर का नगला
		11 केवी बहरोला डी.एस.	6	बामनीखेड़ा, गोपालगढ़, बमारियाका नगला, फूलवाड़ी, बहरोला, अटोहां
		11 केवी मितरोल डी.एस.	5	श्री नगर, मितरोल, औरगांबाद, तुम्मासरा, गुढराणा
3	गुड़गांवा	ढाणा	3	ढाणा, बास कुशला एवं बास हरिया
		मानेसर	1	मानेसर
		चल्लाड़	5	मौजाबाद, जेतपुर, रेणवा, धनौरा एवं चिल्लाड
		आई.बी.पी.	1	मानेसर
		बास खुसला	4	मानेसर, खोह, नैनवाल, कासन
		ढाणी शंकर	7	मुसेपुर, ढाणी लाल सिंह, बिलासपुर, ढाणी शंकर, बिनौला, पथरेड़ी, लगंदा
		जमालपुर	9	खुम्बावास, ततारपुर,ढाणी, चितरासेन, ढाणी खेमूवाली, खरकड़ी, बसलाम्बी, ढाणी रतीराम, जमालपुर, घोशगढ़
		ऊंचा माजरा	6	भोड़ा कलां, ऊंचा माजरा, नरहेड़ा, ढाणी नंदावाली, ढाणी मौथूवाली, ढाणी जीरावाली
		भौरा खुर्द	8	भौरा खुर्द, ढाणी नंगल वाली, नूरपुर, सिधरावाली,

1	2	3	4	5
				रथीवास, भुडका, पालासोली, धीनो खेड़ी
		फरीदपुर	3	फरीदपुर, महचाना, महचाना ढाणी
		जोडीकलां	5	जनौला, जोड़ी खुर्द, सेंपका, जमालपुर, अड़ा, जोड़ी कलां
		लोकड़ी	2	लोकड़ी, दारापुर
		मुमताजपुर	6	सफीनगर, तुरकापुर, ममताजपुर, लोकड़ा, भोकड़ा, बास पदामका
		चमनपुरा	13	हाजीपुर, लोह सिंघानी, चमनपुरा, खरोदा, जालोका, सतलाका, बिलाका, पापरौली, बदखेड़ा, रतियांबाड़ा, रानीयांकीसिंगोला, खूंटपुरी, बिहोगपुर
		राठीवास	5	झामूवास, पारा, फतेहपुर, जोरासी, कलवाड़ी
		भोंडसी	1	भोंडसी
		घामरोज	3	घामरोज, अलीपुर, महंडवाडा
4	नारनौल	सीका डी.एस.	1	सीका
		मंडोला	5	मंडोला, उषमापुर, जरपुर, नंगल माला एवं राजावास
		गिरधरपुर	7	गढ़ी, महासर, गिरधरपुर हसनपुर, कारिया, बोचड़िया एवं खारिवाड़ा
		अकोली डी.एस.	10	सिमली, अकबरपुर, भोजावास, तोताहेड़ी, सिलारपुर, कांवी ढ़ाणी ममराज, मुरारपुर, मुलोडी एवं अकोली
		मोकूता	4	बामनवास, छापड़ा मोकूता, निजामपुर
		भौरी डी.एस.	5	टोबरा, खोर, भोरी, सागरपुर, टिगरा
		यूनिदा डी.एस.	5	उनीन्दा, सलीमपुर, सूजापुर, चांदपुरा, गोकलपुर
		भगदाना डी.एस.	6	भगदाना, माजरा कलां, झोक, लावन, पालड़ी, पनीहर, गरखेड़ा
		बेरी डी.एस.	10	बेरी, भंडोर नीची, भंडोर ऊंची, चमधेड़ा, जन्जरियावास जस्सावास, जटवास, जोनावास, खाड़िया, पेगा

[(श्री मनोहर लाल)]

1	2	3	4	5
		राधा डी.एस.	2	रामबास, ईशराना की ढाणी
5	रेवाड़ी	खुशपुरा	3	खुशपुरा, बलधन कलां एवं बलधन खुर्द
		रामगढ़	7	रामगढ़, मीरपुर, बुढ़ाना, बुढानी, तुरकियावास, गोकलपुर एवं फाड़नी
		अहरोड़	8	अहरोड़, कुंड, मनेथी, पाडला, बासडूडा, ऊंचा, नंगल, जामलपुर एवं ढाणी जोरावत
		भवाडी	10	लालपुर, चुडियावास, डियोधई, गुज्जरीवास, डमलाका, डिवलावास, गज्जीवास, कमालपुर भवाड़ी, नजदीक रेलवे लाईन बिठवाना
		धवाना	1	धवाना
		खोई	1	खोई
		मुरलीपुर	2	गुगोध, मुरलीपुर
		मस्तापुर	6	पलहावास, पहराजवास, सेदपुर चांग, मस्तापुर, टेहना, नया टेहना
		एन.आर.पी.बास	5	ततारपुर, भटसाना, अलावलपुर, एन.आर.पी. बास, खरखाड़ा
		बसाई	10	बनीपुर, इब्राहिमपुर, कमालपुर, खेड़ी मोटला बोयनी, गढ़ी, खातीवास; मुकंदपुर बसाई, लोढ़ाना, बनीपर चोक बावल
		पाली	3	पाली, चिंटा, डूगंरा, ढाणी गुज्जर
6	भिवानी	जुई सिटी	3	जुई खुर्द, जुई बिचाली एवं जुई कलां
		मतानी डी.एस.	5	मीठी, मतानी, मोरकां, ढाणी भाकरां एवं माधोपुरा
		निमार डी.एस.	2	बाधड़ा एवं हंसावास खुर्द
		संजारवास डी. एस.	2	संजारवास एवं फौगाट
		नई हालूवास	1	हालूवास
		बलियाली	1	बलियाली
		डांग खुर्द	3	डांग कलां, डांग खुर्द, बिरान

1	2	3	4	5
		गिकड़ा	1	गिकड़ा
		चांग रोड़	1	चांग रोड
		उत्तम नगर	3	नावा, राजगढ़, धिराना
		मंधाना	1	मंधाना
7	हिसार	तेलांवाली	4	तेलांवाली, कुटियावाली, गुरशल एवं चौधरीवाली
		नई टिब्बा लाईन	5	रायपुर, ढाणी रायपुर, सिकरपुर, नियाना एवं खोखा
		थुराना (डी.एस.)	1	थुराना
		गड़ली (डी.एस.)	2	गड़ली एवं रामसारा
		ग्रामीण (डी.एस.)	6	महमडकी, पिलछियां, खाई, बोरा, नंगल ढाणी एवं लाधूवास ढाणी
		नगथला	1	नगथला
		चिरोड	2	चिरोड़ एवं सिंगरां
		साधांवास आर. डी.एस.	2	साधांवास एवं सिधानी
		पटवार डी.एस.	1	पटवार
		11 केवी मंगाली	3	मंगाली, हरिकोट, कैमारी
		11 केवी गाबीपुर	6	ढाणी-प्रेम नगर, गाबीपुर, बोबूआ, हसनगढ़, कल्लाड-भयानी, खर-खरा
		11 केवी खेदड़	2	खेदड़, देवीगढ़ पूनिया
		11 केवी आर्य नगर	1	आर्य नगर
		प्रेम नगर	8	ढाणी राजू, ढाणी-गुज्जरां, ढाणी-दीपाल, प्रेम नगर, मामन पूरा, दीपाल, ढाणी-पूरियां
		सैनीपुरा	13	सैनीपुरा, बीर फार्म, विराट नगर, बारा सूलेमान, जग्गा बारा, भीम नगर, राजीव नगर, ढाणी बुखारी, ढाणी सोभा, ढाणी कूदनापुर, ढाणी केन्डू, मंदिर बाड़ा
		कुंगर	1	कुंगर

[(श्री मनोहर लाल)]

1	2	3	4	5
8	सिरसा	कंवरपुरा डी. एस.	2	कंवरपुरा एवं कोटली
		मोतीवाला	2	सदेवाला एवं माटूवाला
		बकरियांवाली	3	गुडिया खेड़ा, बकरियांवाली, मोदिया खेड़ा
		शेखूखेड़ा	8	शेखूखेड़ा, हुमांयु खेड़ा, रत्ता खेड़ा, महना खेड़ा, कुंथल, मूसली, उमेदपुरा एवं चिलकनी
		मसीता	5	मौजगढ़, मसीता, ढाणी गोबिन्दगढ़, अलीका एवं लखवाना
		चाक जालू	3	चाक जालू, गौरीवाला एवं रामपुरा बिशनोईयां
		रंगा	1	रंगा
		बंसुधर	3	मीरपुर, अहमदपुर एवं ढाणी सुखचैन
		गांव II डी.एस.	4	मोचीवाली, गडली, कुकरथाना, जोधका
		केलनियां घरेलू	1	केलनियां
		चक्कां आर.डी.एफ., आर.डी.एस.	4	गिंदरां, घोरांवाली, चक्कां, भूना
		हजिरा डी.एस.	3	हंजीरा, रामपुर, ढिल्लों, जोरावाली
		कुटाना डी.एस.	4	बारासाड़ी, रूपावास, रायपुर, धुकरा
		ननुआना आर. डी.एस.	2	ननुआना, मंगालिया
		अबूतगढ़ आर. डी.एस.	4	गोबिन्दपुरा, अबहोली, धामूरा थेर, फिरोजाबाद
		फूलकां आर.डी. एफ.	2	फूलकां, बाजेकां
		हांड़ी खेड़ा आर.डी.एफ.	2	हांड़ी खेड़ा, वेदवाला
		पाना आर.डी. एस.	2	पाना एवं माखा
		सकता खेड़ा	1	सकता खेड़ा
		कोल्ड स्टोर	5	अबूबशहर, सुखेड़ा खेड़ा, राजपुरा माजरा, लोहगढ़ जूतांवाली

1	2	3	4	5
9	जींद	गाटोली डी.एस.	3	गाटोली, जयजेवंती एवं करसोला
		अमरहेड़ी ड़ी. एस.	3	अमरहेड़ी, अहीरका एवं केर खेड़ी
		डबलेन डी.एस.	1	डबलेन
		खापड़ डी.एस.	2	खापड़ एवं भोंगड़ा
		मलिकपुर डी.	2	मलिक पुर एवं धरम गढ़
		11 केवी आर. बधाना डी.एस.	1	बधाना
		11 केवी रामगढ़ आर.डी.एस.	4	रामगढ़, ढाणी, घीमाना, करमगढ़
		11 केवी रसीदां आर.डी.एस.	1	रसीदां
		11 केवी धमताब	1	धमताब
		11 केवी जामनी आर.डी.एस.	4	जामनी, बनिया खेड़ा, तेली खेड़ा, रिटोली
10	फतेहाबाद	बिसला	5	स्वामी नगर, मताना, माजरा, बिसला, बरसीन
		भारपुर	3	भारपुर, हमजापुर, ढाणी सुंदर नगर
		मताना-II	5	बिघर, मानावाली, बनगांव, बोदियाखेड़ा, ढ़ाणी मियाखां
		बलियाला	4	बलियाला, सरदारेवाला, लाडूवास, नंगल ढाणी
		नंगला	3	नंगला, नंगली, लालोढ़ा
		लाखूवाली ढाणी	5	गुलरवाला, धीर, काना खेड़ा, लाखूवाली ढाणी, शकरपुरा
		गाजूवाला	5	हांसावाला, मदनपुरा, कुंदनपुरा, शकरपुरा, मुगलपुरा
11	मेवात	11 केवी अलदुका डी. एस.	10	सालाहेड़ी, मणकी, बजारका, छछेड़ा, छपेड़ा, कीड़ा, पोंडराई, ए.पी. नतोल, अलदुका, कुरथला
		11 केवी डोंडल	3	बदेड़, नीम खेड़ा, डोंडल

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3	4	5
		11 केवी लाहाबास		5 लाहाबास, कतपुरी, मो. पुर, तेर, एफ.पी. मीओ
		कुल	**524**	
कुल योग (उ.ह.+द.ह.)			**1038**	

गांवों का विवरण जहां सप्लाई 15 से 18 घंटे तक बढ़ा दी गई है

क्र.सं.	सर्कल का नाम	फीडर का नाम	गांवों की संख्या	गांवों के नाम
1	अम्बाला	शाहपुर	2	शाहपुर एवं मछौंदा
		रायवाली	4	रायावाली, गाजीपुर, शामरू एवं तेपला
		टिकरी	5	धारडा पंचायत धरती पंचायत, नेयता पंचायत, टिपरा पंचायत एवं कोटी
2	करनाल	डाबडी	1	डाबडी
		गालिबखेड़ी	3	गालिबखेड़ी, चंदर खेड़ा एवं दयालपुरा
3	गुडगांव	बार गुज्जर	2	नौरंगपुर एवं बारगुज्जर
4	सिरसा	तलवाड़ा	2	तलवाड़ा एवं मौजू की ढाणी
		बिज्जूवाली	5	गोदिकां, दारेवाला, बिज्जूवाली, मूनवाली एवं चकफरीदपुर
		खटरावन	1	खटरावन
	कुल		**25**	

बी) हां श्रीमान इन गांवों के उपभोक्ताओं द्वारा नियमित रूप से जमा करवाए जा रहे बिजली बिलों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

फीडर का नाम	गांवों की संख्या	जगमग गांव योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए इन गांवों में उपभोक्ताओं की संख्या	जुलाई-15 से जनवरी-16 तक नियमित रूप से अपने बिलों को अदा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या	अपने बिलों को नियमित रूप से अदा करने वाले उपभोक्ताओं की %ता
1	2	3	4	5
उ.ह.बि.वि.नि.				
अम्बाला	94	3101	2542	81.97%
झज्जर	8	5196	3491	67.19%
कुरुक्षेत्र	19	5244	4487	85.56%
करनाल	16	5103	3606	70.66%

1	2	3	4	5
पानीपत	5	3281	2650	80.77%
रोहतक	8	8836	6068	68.67%
सोनीपत	11	6897	4796	69.54%
कैथल	7	2976	2223	74.70%
यमुनानगर	31	6935	4601	66.34%
कुल उ.ह.बि.नि.	**199**	**47569**	**34464**	**72.45%**
द.ह.बि.वि.नि.				
फरीदाबाद	7	8171	6624	81.07%
पलवल	59	14689	11670	79.45%
गुडगांव	11	6332	5760	90.97%
नारनौल	23	5320	4663	87.65%
रेवाड़ी	18	6894	4357	63.20%
भिवानी	14	8701	4965	57.06%
हिसार	24	14280	10055	70.41%
सिरसा	35	13034	7557	57.98%
जींद	11	6860	3531	51.47%
कुल उ.ह.बि.वि.नि.	**202**	**84281**	**59182**	70.22%
कुल योग (उ.ह.+द.ह.)	**401**	**131850**	**93646**	71.02%

To Regularize the Temporary Employees

252. Shri Pirthi Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the temporary employees working as water careers and sweepers in dispensaries of AYUSH Department togetherwith the time by which these employees are likely to be reularized.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी,

To Open Gangoli Link Drain

278. Shri Jasbir Singh : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the Gangoli link drain for irrigation falling under the Safidon Assembly constituency ?

सिंचाई मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी। धारा-11 व धारा-19 के अधीन भूमि के कागजात की अधिसूचना जारी हो चुकी है और मुआवजा शीघ्र दिए जाने की संभावना है। इसके पश्चात् ड्रेन को खोल दिया जाएगा। सर, इसके अलावा में यह भी बताना चाहूंगा कि गंगोली लिंक ड्रेन को गांव मोरखी के जमींदारों ने भूमि का मुआवजा न मिलने की वजह से अपनी सीमा में बंद कर रखा है। इस ड्रेन के भूमि के मुआवजा से सम्बन्धित धारा-11 व धारा-19 के कागजात सरकार द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं और अधीक्षक अभियन्ता, यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है जिसकी अधिसूचना व अखबार की प्रकाशित प्रतियां जिला राजस्व अधिकारी जीन्द को भेज दी गई है। अब आयुक्त हिसार द्वारा भूमि के रेट निर्धारित किए जाने हैं।

जमीन का भुगतान करने के पश्चात दिनांक 30-06-2016 तक ड्रेन को खोल दिया जाएगा।

Total Amount of Loan/Advances

257. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Finance Minister be pleased to state the total amount of loan/advances taken by the State/ Government since April, 2006 together-with year-wise breakup along-with various sources and the steps taken by the government to repay the aforesaid loans ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी,

(i) अप्रैल, 2006 से सरकार द्वारा लिए गए ऋण/अग्रिम का वर्ष वार ब्यौरा :–

(₹ करोडों में)

क्रं. सं.	वर्ष	कुल ऋण	बाजारी ऋण	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, से ऋण	ब्राह्य सहायता परि-योजनाओं से ऋण	अन्य
1	2006-07	2011.89	Nil	1175.87	-	-	-	-
2	2007-08	843.50	Nil	1715.00	-	-	-	-
3	2008-09	3888.07	2795.00	1065.50	285.62	492.99	-	-
4	2009-10	8455.37	4000.00	806.10	269.72	558.51	123.54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	2010-11	10513.21	4450.0	1312.42	203.70	567.34		223.56	-
6	2011-12	11741.10	6356.65	141.69	264.53	356.88		156.66	-
7	2012-13	15560.31	9330.00	438.40	322.38	335.73		73.86	-
8	2013-14	17712.95	11446.18	566.60	398.85	353.44		290.77	-
9	2014-15	18858.75	13200.00	1251.31	467.76	186.97		118.11	-
10	2015-16 (फरवरी तक)	16201.75	14100.00	1605.37	218.73	120.82		156.83	-
	योग	**105786.90**	**65677.13**	**10078.26**	**2431.29**	**2972.68**		**1143.33**	-

(ii) वर्ष-दर-वर्ष ऋण अदायगी का विवरण :–

(₹ करोड़ों में)

क्रं. संख्या	वर्ष	ब्याज/मूलधन अदायगी
1.	2006-07	2265.06/1113.77
2.	2007-08	2345.77/840.92
3.	2008-09	2338.91/1191.83
4.	2009-10	2736.53/2745.97
5.	2010-11	3318.56/4641.56
6.	2011-12	4000.81/5011.40
7.	2012-13	4744.48/6298.14
8.	2013-14	5849.77/8077.26
9.	2014-15	6928.27/8227.41
10.	2015-16	8563.75/8580.14

———————

Problem of Drinking Water

266. Shri Kehar Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state–

(a) whether it is a fact that the underground water is saline in Hathin area District Palwal; and

[Shri Kehar Singh]

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to install deep tubewells in the said area to provide pure water for dringking togetherwith details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) जी हां श्रीमान् जिला पलवल के हथीन क्षेत्र तथा पलवल मण्डल के कुछ गांवों में भूमिगत जल खारा है।

(ख) जिला पलवल में 263 गांव हैं, जिनमें हथीन निर्वाचनक्षेत्र के 103 गांव सम्मिलित हैं। हथीन निर्वाचनक्षेत्र के 100 गांवों में पानी खारा है। जिनमें से 79 गांव पहले ही रैनीवैल सैगमैन्ट के अन्तर्गत यमुना बाढ़ समतल क्षेत्र गांव रहीमपुर में रैनीवैल तथा गहरे नलकूप लगाकर 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से कवर किए जा चुके हैं। हथीन निर्वाचनक्षेत्र के शेष 21 गांवों, जहां पानी खारा है, के लिए जिला पलवल व फरीदाबाद के 84 गांवों में पेयजल की बढ़ोतरी के लिए गहरे नलकूप लगाने तथा रैनीवैल पर आधारित 185.00 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा इस परियोजना के पूरा होने के बाद इन 21 गांवों में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त रैनीवैल सैगमैन्ट के अन्तर्गत कवर किए गए कुछ गांव पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए दो अनुमानों, गांव खिलूका में 494.00 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त मध्यवर्ती बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण, जिसमें गांव खिलूका, कोट, ढाणी मिठाका, गुराकसर, गोहपुर, ढाणी मालपुर शामिल हैं तथा गांव फिरोजपुर राजपूत में 768.00 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त मध्यवर्ती बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण, जिसमें गांव फिरोजपुर राजपूत, गढी बिनोदा, धिरगराका, खांडावाली, बुराका हथीन, मलोखरा, मंगोरका (मनमोलाका), सनपनकी, बिचपुरी, जलालपुर खालसा, कलसारा, भंगूरी शामिल हैं, का प्रशासकीय अनुमोदन हो चुका है और धनराशि की उपलब्धता अनुसार कार्य 31-10-2017 तक पूरे होने की संभावना है।

To Erect the Iron Mesh Adjacent to the Forest

236. Shri Hari Chand Middha : Will the Forest Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to erect the iron mesh alongside the road adjacent to the forest (Bir) on the Hansi road in Jind city; and

(b) if so, the time by which it is likely to be erected ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां श्रीमान जी , जीन्द शहर में हांसी रोड़ पर वन (बीड़) के साथ-साथ लोहे की जाली लगाने का कार्य जारी है।

(ख) यह कार्य जून, 2016 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

———————

To Set-up Industry

284. Shri Ravinder Baliala : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any industry in Ratia Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be set up ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान जी,

संतुलित क्षेत्रीय विकास की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा उधम प्रोत्साहन नीति 14-08-2015 को अधिसूचित की गई जिसमें भोगोलिक सवितरण के अधार पर प्रोत्साहन (श्रेणी 'ग' और 'घ' में) प्रस्तुत किया है। रतिया विधानसभा क्षेत्र 'ग' ब्लॉक में आता है। अपेक्षित है कि रतिया विधानसभा क्षेत्र में इस निति में दिए गए लाभों का फायदा होगा।

———————

To Start Science faculty

298. Shri Rajdeep Phogat : Will the Education Minister be pleased to state the time by which the science faculty in Government College Baund is likely to be started ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बौंद कलां में विज्ञान संकाय आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———————

Category-wise Backlog of the Posts of SC/BC

337. Shri Udai Bhan : Will the Minister of State for Welfare of SC/BC be pleased to state.

Backlog of the posts of the employees belonging to scheduled castes and backward classes in the Government offices, Semi Government Departments, Boards and Corporatons togetherwith the steps being taken by the Government to fill up these posts alongwith the details thereof ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : श्रीमान जी, बैकलॉग की स्थिति पूर्ण विवरण सहित विधान सभा के पटल पर रखी है।

विवरण

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित कर्मचारियों का विभिन्न सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में श्रेणीवार उपलब्ध बैकलॉग दिनांक 31-12-2012 तक का विवरण निम्न प्रकार से है।

[श्री कृष्ण कुमार बेदी]

(क) अनुसूचित जाति

	ग्रुप-ए0	ग्रुप बी0	गुप-सी0	ग्रुप डी0
विभाग	172	516	6691	478
अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों	45	44	1280	332
कुल जोड़	**217**	**560**	**7971**	**810**

(ख) पिछड़े वर्ग

	ग्रुप-ए0	ग्रुप बी0	गुप-सी0	ग्रुप डी0
विभाग	02	40	3914	1049
अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों	08	21	858	439
कुल जोड़	**10**	**61**	**4772**	**1488**

(ग) बैकलॉग को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 22/33/2012-1 जी0एस0-III दिनांक 24-09-2013, दिनांक 27-5-2014 तथा दिनांक 11-09-2015 द्वारा सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों तथा विश्वविद्यालयों को हिदायतें जारी की गई है जिसमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बैकलॉक को पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। यद्यपि यह एक लम्बी प्रक्रिया है क्योंकि विभिन्न नियोक्ता एजैन्सीज जैसे:- हरियाणा लोक सेवा आयोग को ग्रुप 'क', 'ख' तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप 'ग', 'घ' के लिए मांग भेजी जाती है और यह आवेदकों की योग्यता तथा अनुभव पर भी निर्भर करती है। इसलिए इस कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती लेकिन राज्य सरकार इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

Regularization of Illegal Colonies

332. Dr. Pawan Saini : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the illegal colonies in state; if so, the time by which illegal colonies are likely to be regularized ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नहीं, श्रीमान।

जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में गांव इगरा से दो लड़कियों के अपहरण मामला उठाना

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कन्याओं के ऊपर ब्यान दे रहे थे इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण इशू का यहां जिक्र करना चाहूंगा। कल के अखबार में पुलिस महानिदेशक का एन.डी.आर.आई., करनाल से ब्यान आया है कि हम लड़कियों को बचाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव इगरा की दो लड़कियों

को दिनांक 2.3.2016 को उठा लिया गया है । इस केस में एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गई है लेकिन पुलिस कोई कारवाई नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र ढुल जी, जिस दिन वित्त मंत्री जी बजट पेश करते हैं उस दिन जीरो आवर नहीं होता है इसलिए आप अपनी बात फिर रख लेना।

सदन के कार्य में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले से तय सदन की कार्यसूची के मुताबिक वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमानों के सम्बन्ध में हरियाणा विनियोग संख्या-1 विधेयक, 2016 दिनांक 30 मार्च, 2016 को रखा जाना है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी के आग्रह पर इस विधेयक का पास होना सरकारी कार्यों के निपटारे के लिए अति आवश्यक है इसलिए यह विधेयक सदन के पटल पर पास होने के लिए 22 मार्च, 2016 को पेश किया जाएगा। यदि हाउस की सहमति हो तो हरियाणा विनियोग संख्या-1 विधेयक, 2016 जोकि पहले दिनांक 30 मार्च, 2016 को सदन में पेश किया जाना था, के बजाय अब यह 22 मार्च, 2016 को पेश कर दिया जाए।

आवाजे : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हरियाणा विनियोग संख्या-1 विधेयक, 2016 जोकि पहले दिनांक 30 मार्च, 2016 को सदन में पेश किया जाना था, के बजाय अब यह 22 मार्च, 2016 को पेश किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री महोदय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में राज्य का वर्ष 2016–17 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. इस गरिमामय सदन का सदस्य होना मेरे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है, जिससे मुझे प्रदेश के लोगों की सेवा करने तथा हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

3. बजट मात्र आंकड़े प्रस्तुत करने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सरकार के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति और प्रदेश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने का दस्तावेज़ है। इसलिए मैं, इस अवसर पर सरकार के विकास दृष्टिकोण और प्रदेश में उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने की दीर्घावधि रणनीति प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

4. सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 2015–16 के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने जा रही है और निराशाजनक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बावजूद राष्ट्र स्थायित्व और विकास के मजबूत स्थल के रूप में उभरा है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

5. योजना आयोग के स्थान पर National Institution for Transforming India – नीति आयोग बनाया गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह आयोग, केन्द्र और राज्यों को सहकारी संघवाद के अनूठे मॉडल में एक संघठनात्मक टीम के रूप में कार्य करने का मंच उपलब्ध करवाता है। अपने अस्तित्व के दूसरे वर्ष में, नीति आयोग नवप्रवर्तन और ज्ञान के केन्द्र के रूप में उभरेगा, जोकि ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कुशल मार्गदर्शन करेगा।

6. राज्य सरकार केन्द्रीय करों का मुक्त हस्तांतरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने तथा कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का स्वागत करती है। इससे 'सबको एक ढांचे में ढालने' की पुरानी नीति में यह एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है और राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी विकास की योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में अपेक्षित उदारता देने की हरियाणा जैसे राज्यों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है। इसके साथ ही हम 2017–18 से योजना और गैर–योजना के बीच कृत्रिम अंतर को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2016–17 में की गई घोषणा का भी स्वागत करते हैं। निःसंदेह केन्द्र और राज्यों को पूंजीगत तथा राजस्व खर्च में अंतर बनाए रखने की कार्यप्रणाली पर मिलकर काम करना होगा।

वृहत् आर्थिक परिप्रेक्ष्य

7. 'सबका साथ–सबका विकास' का मूलमंत्र प्रदेशवासियों में किसी जाति, धर्म या समुदाय का भेदभाव किये बिना, सभी भौगोलिक क्षेत्रों के संतुलित, त्वरित और समान विकास की सोच को वास्तविकता में बदलने की सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक है।

2015–16 में विकास प्रदर्शन

8. हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से निरन्तर अधिक रही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2015–16 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि 2014–15 में 8.0 प्रतिशत और 2013–14 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2014–15 में 7.2 प्रतिशत और 2015–16 में 7.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2015–16 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,65,204 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2014–15 में 1,50,260 रुपये थी।

9. हम में से कई लोगों का मानना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान को हमारे सांख्यिकीय आंकड़ों में ठीक से परिलक्षित नहीं किया जा रहा था। अब, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने इसे सही माना है और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संरचनात्मक ढांचे में बदलाव किया है। नई कार्य प्रणाली और वर्ष 2004–05 की बजाय 2011–12 के संशोधित आधारभूत आंकड़ों के अन्तर्गत 2012 में की गई नई पशुधन गणना तथा फसलों और पशु उत्पादों के बाजार मूल्यों में बढ़ोतरी के चलते, 2013–14 में स्थिर मूल्यों पर हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 5.6 प्रतिशत से भी

अधिक होना दर्शाया गया है, जो पूर्व अनुमानों से अधिक है। नए सूत्र के अनुसार, 2015–16 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 18.2 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 30.5 प्रतिशत, जबकि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 51.3 प्रतिशत है।

10. प्राथमिक क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर 2014–15 में 0.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के समक्ष 2015–16 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए उल्लेखनीय सुधार हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र में 2015–16 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2014–15 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रमुख चुनौतियां

11. जब हम सभी अपने प्रिय राज्य हरियाणा के गठन की स्वर्ण जयंती मनाने के बारे में सोच रहे थे, तो हाल ही में राज्य में हिंसा और सेवाओं में बाधा रूपी काले बादल छा गये। हम हिंसा के पीछे षड्यंत्र की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने उन भाइयों के आँसू पोंछने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं, जो इस निंदनीय हिंसा के शिकार हुए हैं। हम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा इस सौभाग्यशाली पुण्य धारा के मेहनती लोगों को समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

अटल जी की पंक्तियों में–

''हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में,
नतमस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में ढ़लना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा।''

12. यदि मैं मार्च, 2015 में हमारे द्वारा दो खंडों में जारी किये गये श्वेत–पत्र में दर्शायी गई चुनौतियों का उल्लेख नहीं करता हूँ, तो यह मेरे कर्तव्य में कोताही मानी जाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा अवरोध दोनों बिजली वितरण कम्पनियों (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) का अत्यधिक संचित घाटा रहा है, जोकि 2004–05 के 1030 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013–14 में 26,912 करोड़ रुपये हो गया। इन दोनों कम्पनियों का संचित ऋण 31 मार्च, 2004 को 1458 करोड़ रुपये था, जोकि 31 मार्च, 2014 को बढ़कर 28,199 करोड़ रुपये हो गया। कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे जोकि वर्ष 2005–06 में 38 प्रतिशत थे, 2011–12 में घटकर 25.54 प्रतिशत हो गये, परन्तु 2013–14 में ये पुनः बढ़कर 29.42 प्रतिशत हो गये।

13. हरियाणा सरकार व भारत सरकार के मध्य हुए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) पर समझौते के अनुसार बिजली वितरण कम्पनियों का संचित ऋण, जो 34600 करोड़ रुपये है, का 75 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार को दो वर्षों के भीतर अपने ऊपर लेना होगा, ताकि बिजली कम्पनियों पर ब्याज व ऋण का बोझ कम किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, अब राज्य सरकार ने 2015–16 और 2016–17 में दो किस्तों में 25,950

[कैप्टन अभिमन्यु]

करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया है। चूंकि डिस्कॉम के भारी कर्ज के इस अधिग्रहण से राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ऋण और ब्याज से संबंधित सूचकांक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएंगे, भारत सरकार ने इस सीमा को दो वर्षों अर्थात् 2015–16 और 2016–17 के लिए खत्म कर दिया है। तदनुसार, संशोधित अनुमान 2015–16 के लिए इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमान तथा बजट अनुमान, जोकि मैं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इस एकमात्र निर्णय से काफी प्रभावित हुए हैं।

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवें वेतन आयोग ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। हम भारत सरकार द्वारा अंगीकार किये गये वेतनमानों और भत्तों का प्रायः अनुसरण करते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लेने के उपरांत हम हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव करते हैं। इसके लिए 2016–17 के बजटीय अनुमानों में उपयुक्त प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि दस साल में एक बार किये जाने वाले इस संशोधन से हमेशा राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है।

15. हालांकि, वर्ष 1966 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर हरियाणा के 50 वर्षों के सफर को धूमधाम से मनाने के लिए राज्य सरकार गहन परामर्श के बाद विस्तृत योजनाएं बनाने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में, मैं और मेरे साथी, विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जाने वाली कई स्वर्ण जयंती योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसी योजनाओं में से कुछ की सूची बजट दस्तावेजों में दी गई है।

बजट अनुमान 2016–17

16. महोदय, बजट अनुमान 2015–16 के अनुसार कुल बजट 69,140 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2016–17 में पिछले वर्ष से 28.4 प्रतिशत की वृद्धि करके 88,781.96 करोड़ रुपये करने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। इसमें 40,256.21 करोड़ रुपये (45.3 प्रतिशत) का योजनागत परिव्यय और 48,525.75 करोड़ रुपये (54.7 प्रतिशत) का गैर–योजनागत परिव्यय शामिल है। महोदय, जैसाकि मैंने पहले वर्णन किया है इस वर्ष के मेरे बजट के कुछेक सकल अनुमानों को दो भागों में बांटा जाएगा, नामतः 'उदय' और 'उदय के बिना'। इसी तरह की पद्धति दूसरे अधिकांश राज्यों द्वारा सहज समन्वय व तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अपनाई जाती है। यदि मैं बिजली वितरण कम्पनियों के संचित ऋण की 75 प्रतिशत की वित्तीय अधिग्रहण छूट के बाद 2016–17 के बजट अनुमानों के आंकड़ों की तुलना 2015–16 के साथ करूँ, तो 2016–17 के 78,185.96 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमानों में 2015–16 के संशोधित अनुमान 67,737.30 करोड़ रुपये की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं।

योजनागत परिव्यय

17. मैं वार्षिक योजना 2016–17 के लिए 'उदय' के बिना 31,606.21 करोड़ रुपये के कुल

परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2015–16 के 25,743.46 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय अनुमानों से यह 22.77 प्रतिशत की वृद्धि है।

18. उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 10,141.78 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों द्वारा 1048.84 करोड़ रुपये का बजटेत्तर परिव्यय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के बजटीय संसाधनों से 1253.84 करोड़ रुपये विकास गतिविधियों पर खर्च किये जाएंगे।

गैर–योजनागत परिव्यय

19. मैं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 48,525.75 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, इसमें 'उदय' का प्रावधान भी शामिल है, जोकि वर्ष 2015–16 के लिए 42,294.28 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 'उदय' के बिना यह 46,579.75 करोड़ रुपये है, जोकि 2015–16 के संशोधित अनुमान 42,294.28 करोड़ रुपये की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कुल राजस्व प्राप्तियां (टी.आर.आर.)

20. संशोधित अनुमान 2015–16 के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां 54,167.35 करोड़ रुपये संभावित हैं, जिसमें कर राजस्व 40,436.10 करोड़ रुपये और गैर–कर राजस्व 13,731. 25 करोड़ रुपये है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल राजस्व प्राप्तियां 2014–15 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2015–16 में 10.7 प्रतिशत अनुमानित हैं।

21. बजट अनुमान 2016–17 में, कुल राजस्व प्राप्तियां 62,955.53 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिनमें से कर राजस्व 46,388.31 करोड़ रुपये और गैर–कर राजस्व 16,567.22 करोड़ रुपये है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल राजस्व प्राप्तियां 2016–17 में 10.7 प्रतिशत अनुमानित हैं।

22. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय, विपक्ष के मेरे कुछ मित्रों ने बजट अनुमानों की प्रशंसा की थी और साथ ही यह भी आशंका व्यक्त की थी कि इन अनुमानों में प्रक्षेपित राज्य का अपना कर राजस्व हासिल करना सम्भव नहीं होगा। मुझे इस गरिमामय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा की जनता की उद्यमिता व मेहनत के कारण हुआ प्रदेश का आर्थिक विकास, संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक प्रयास, कम्प्यूटरीकरण, बढ़ी पारदर्शिता व जवाबदेही और नियमित निगरानी व पैरवी की मदद से उच्च संग्रहण क्षमता और संसाधनों की चोरी को रोक कर हमने अपने राजस्व संग्रहण के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जो हमने निर्धारित किए थे। मुझे इस गरिमामय सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के स्वयं के कर संसाधनों व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2014–15 के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया, जो कि एक उल्लेखनीय वृद्धि है। यहां यह तथ्य अति महत्त्वपूर्ण है कि 2015–16 की इस वृद्धि से पहले के चार वर्षों में यह अनुपात 2011–12 से गिरावट का रूझान दर्शा रहा था। मैं आशा करता हूँ कि 2016–17 में यह अनुपात लगभग उसी स्तर पर रहेगा।

[कैप्टन अभिमन्यु]

राजकोषीय घाटा

23. बजट अनुमान 2015–16 में, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत अनुमानित था। हालांकि, संशोधित अनुमान 2015–16 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद ('उदय' के बिना) का 2.58 प्रतिशत अनुमानित है। राजकोषीय समेकन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप 2016–17 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद ('उदय' के बिना) के 2.47 प्रतिशत पर रहने की सम्भावना है। यह पूरी तरह से 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर है।

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के वृहत् आर्थिक प्रबन्धन से राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे इत्यादि जैसे आर्थिक मानकों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन प्रयासों की लोकप्रिय समाचार पत्रिका इंडिया टूडे जैसी स्वतंत्र एजेंसियों ने सराहना की है, जिसने 'स्टेट ऑफ दि स्टेट्स कॉन्क्लेव–2015' में पर्यावरण तथा वृहत् अर्थव्यवस्था की दो श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश को सर्व श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। वृहत् अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मुझे आपको यह जानकारी देते हुए गर्व एवं हर्ष हो रहा है कि हरियाणा का क्रम 2013–14 में 12वें स्थान से 2014–15 में प्रथम स्थान पर पहुंच गया।

पूंजीगत व्यय

25. महोदय, इस गरिमामय सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष राज्य की अर्थव्यवस्था पर श्वेत–पत्र तथा 2015–16 का बजट प्रस्तुत करने के बाद, हमने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु एक उपाय के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात में सुधार लाने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दिशा में कार्य शुरू हो गया है। पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2014–15 के 4,558.40 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 ('उदय' के बिना) में 6,769.30 करोड़ रुपये की वृद्धि का रूझान दर्शाया गया है, जोकि 48.5 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, 2015–16 में पांच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हुडा, एचएसआईआईडीसी, एचएसएएमबी, एचडब्ल्यूसी और बिजली कम्पनियों) द्वारा बुनियादी ढांचे के सृजन पर 5006.54 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार, 2015–16 में कुल पूंजीगत परिव्यय के रूप में 11,775.83 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

26. मैं, 'उदय' के बिना 2016–17 में पूंजीगत निवेश बढ़ाकर 8788.58 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों से 29.8 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, 2016–17 में इन पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 6990.38 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। कुल मिलाकर वर्ष 2016–17 में पूंजीगत व्यय 15,778.96 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो कि वर्ष 2015–16 से 33.99 प्रतिशत अधिक है।

नई पहलें

27. महोदय, हमने राज्य की निधियों का सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने तथा पूरी

प्रणाली को और अधिक दक्ष तथा किफायती बनाने के लिए उच्च स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से कई उपाय किये हैं। धन के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विभागों द्वारा राज्य के खजाने से बाहर बैंक खातों में धन जमा करवाने से बचने के लिए सरकार ने पर्सनल लेजर अकाउंट (पीएलए) खोलने का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धन राज्य के खजाने में रहे और खजाने से पैसा केवल तभी निकाला जाए, जब वास्तव में आवश्यकता हो।

28. मैं ऋण और नकदी प्रवाह की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए वित्त विभाग में एक ऋण और नकदी प्रबंधन प्रकोष्ठ (Debit and Cash Management Cell) की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य सभी बकाया ऋणों तथा उन पर ब्याज, ऋणों की अवधि, पुनर्भुगतान अनुसूची आदि का अभिग्रहण करना तथा प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर बेहतर तथा पारदर्शी ढंग से भविष्य में ऋण लेना सुविधाजनक बनाना होगा। यह प्रकोष्ठ अन्य कार्यों के अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए अधिशेष निधियों के निवेश की सम्भावनाएं भी तलाशेगा।

29. मैं 'स्वर्ण जयन्ती वित्त नीति संस्थान' नामक एक राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह संस्थान सरकार, व्यापार जगत, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं परामर्श संगठनों के सदस्यों को सार्वजनिक वित्त एवं नीति के क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ हरियाणा सरकार और अन्य राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी विशिष्ट प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाएगा।

30. यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों व निगमों की भूमि का विशाल भाग अप्रयुक्त पड़ा है या उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। यह राज्य के लिए राजस्व का एक संभावित स्रोत है, जिसका उचित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य संसाधनों का परिसम्पत्ति मानचित्रण एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का उचित लेखा–जोखा भी अनिवार्य है। राज्य के लोगों के हित में और अधिक राजस्व जुटाने के लिए राज्य सरकार भूमि के इन हिस्सों का प्रभावी उपयोग करने या मुद्रीकरण के सुझाव प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही योग्य एवं स्वच्छ छवि के व्यक्तियों की एक कमेटी गठित करेगी।

31. हाल ही में, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आवास ऋण, वाहन ऋण, कम्प्यूटर ऋण, उपभोक्ता उपयोग की टिकाऊ वस्तुओं तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के राज्य सरकार के कार्य को बैंकों को सौंपने से संबंधित एक स्कीम स्वीकृत की है। इस स्कीम से सभी पणधारियों नामतः कर्मचारियों और सरकार को लाभ होगा। इस स्कीम के तहत सभी सरकारी कर्मचारी सरकार की वर्तमान शर्तों के आधार पर बैंकों से ऋण सुविधा ले सकेंगे। सरकार इस बचत का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए कर सकेगी।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रकोष्ठ

32. सरकार ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर परियोजनाएं क्रियान्वित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सड़क क्षेत्र में कुण्डली–मानेसर–पलवल सड़क परियोजना पीपीपी पद्धति पर क्रियान्वित की जा रही एक मुख्य परियोजना है। इसके

[कैप्टन अभिमन्यु]

अतिरिक्त, सरकारी अस्पतालों में हीमोडायैलिसिस इकाइयां, सी.टी. स्कैन सुविधाएं स्थापित करने, ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करने, फरीदाबाद, करनाल में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बस अड्डे विकसित करने आदि जैसी अनेक परियोजनाएं पीपीपी पद्धति में क्रियान्वित की जा रही हैं। जिला मेवात में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर 14.28 किलोमीटर लम्बी फिरोजपुर झिरका–बीवन सड़क को दो मार्गी बनाने की प्रक्रिया बोली आमंत्रित करने के स्तर पर है।

33. सरकार द्वारा पीपीपी पद्धति के लिए चिह्नित किए गए छः प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य देखभाल, सड़क एवं परिवहन, पर्यटन, शहरी आधारभूत संरचना, पानी एवं स्वच्छता तथा शिक्षा एवं कौशल विकास में प्रस्ताव आग्रह (RFP) एवं योग्यता आग्रह (RFQ) तैयार करने में विभागों की मदद करने के लिए कारोबार सलाहकारों (Transaction Advisors) का एक पैनल गठित किया जा रहा है। मैं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता को सुधारने के लिए और इस प्रणाली को औपचारिक रूप देने हेतु वित्त विभाग में एक स्थायी पीपीपी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

क्षेत्रवार आबंटन

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

34. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमें विदित है कि कृषि क्षेत्र के समक्ष आई चुनौतियों के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र को एक लम्बी अवधि तक संकट का सामना करना पड़ा है। यह देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पांच वर्षों के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की घोषणा की है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर आश्रित लोगों की स्मृद्धि का सीधा सम्बन्ध प्रदेश की खुशहाली से है। तदानुसार, हमारी सरकार ने भी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का आबंटन संशोधित अनुमान 2015–16 के 11,444.41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2016–17 में 13,494 करोड़ रुपये किया है। (इस समय मेजे थपथपाई गई) कृषि क्षेत्र को दिया महत्त्व यह तथ्य दर्शाता है कि आबंटित राशि सम्पूर्ण बजट अनुमानों का 13.71 प्रतिशत है।

35. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत जहां कृषि का आबंटन वर्ष 2016–17 में 736.66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 984.51 करोड़ रुपये किया है, वहीं बढ़े हुए आबंटन के साथ तालमेल बैठाते हुए, मैं राज्य का हिस्सा भी बजट अनुमान 2015–16 के 132.83 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 205.20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। (इस समय मेजे थपथपाई गई) यह 54.48 प्रतिशत वृद्धि होगी। राज्य में जल संरक्षण प्रौद्योगिकी, समेकित वाटरशैड विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम और सेम प्रभावित क्षेत्रों के सुधार की एक परियोजना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आबंटन में समुचित वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और सॉयल हैल्थ कार्ड जैसी केन्द्रीय योजनाओं के तहत भी आबंटन को 4.56 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15.02 करोड़ रुपये किया गया है। बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न

योजनाओं हेतु मैं बजट अनुमान 2015–16 के 239.45 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2016–17 में 378.44 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आबंटन का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि 58.04 प्रतिशत अधिक है।

36. करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, मैं प्रथम भाग में 50 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

37. मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान को भी बजट अनुमान 2015–16 के 336.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2016–17 में 368.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

38. किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार ने प्रति एकड़ मुआवज़ा दर ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बाढ़, जल भराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और सफेद मक्खी के प्रकोप आदि के कारण क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवज़ा देने का दायरा भी बढ़ाया है। किसानों को रबी 2015 के लिए लगभग 1092 करोड़ रुपये मुआवज़े के तौर पर वितरित किए गए, वहीं वर्ष 2013 और 2014 की 268.93 करोड़ रुपये की बकाया मुआवज़ा राशि भी वितरित की। सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण जिन किसानों की कपास की फसल खराब हो गई थी, उन्हें मुआवज़ा देने के लिए 967 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस वर्ष में सरकार ने किसानों को कुल 2327.93 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित की है। यह हरियाणा राज्य के इतिहास में मुआवज़े की सर्वाधिक मात्रा है, प्रति एकड़ मुआवज़े की अधिकतम राशि है और सर्वाधिक क्षेत्र के लिए दिया गया मुआवज़ा है।

39. राज्य कृषि आधारभूत संरचना के सृजन और फसलों के विपणन के लिए अनेक कदम उठा रहा है। वर्ष 2014–15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 152.36 लाख मीट्रिक टन (47.32 लाख मीट्रिक टन खरीफ खाद्यान्न और 105.04 लाख मीट्रिक टन रबी खाद्यान्न) रहा। खराब मौसम के बावजूद हरियाणा के मेहनतकश किसानों ने प्रदेश के अन्न भंडारों को भरा और राज्य दोबारा केन्द्रीय पूल में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश बना। इसके फलस्वरूप, राज्य को वर्ष 2014 में भारत के राष्ट्रपति से प्रशस्ति पुरस्कार और वर्ष 2014–15 में चावल उत्पादकता के लिए 'कृषि कर्मण पुरस्कार' मिला है।

40. हम कृषि क्षेत्र के नुकसान की भरपाई और ग्रामीण क्षेत्रों में परिणामी दबाव को कम करने के लिए शुरू की गई ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' नामक नई कृषि बीमा योजना का स्वागत करते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत सहायक होगी। इस नई योजना के लिए मैं वर्ष 2016–17 में 300 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

41. सरकार किसानों की उत्पादन लागत को कम करने और कृषि गतिविधियों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए उन्हें सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति कर रही है। वर्ष 2015–16 में 6425.90 करोड़ रुपये की राशि सबसिडी के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है और इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2016–17 में 6800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

सिंचाई

42. पानी का समुचित उपयोग करने के लिए इसकी हर एक बूंद का संरक्षण करना अत्यावश्यक है, क्योंकि टिकाऊ कृषि विकास के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण घटक है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के ''हर खेत को पानी'' उपलब्ध करवाने के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेक नई पहल की जा रही हैं। इनमें कुछेक हैं –143 करोड़ रुपये की लागत से जे.एल.एन. उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता को सुधारना, 300 करोड़ रुपये की लागत से 565 जल मार्गों का सुधार, 291.64 करोड़ रुपये की लागत से 75 सिंचाई नहरों एवं माइनरों के विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की परियोजनाएं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छः जिलों नामतः अम्बाला, सोनीपत, झज्जर, सिरसा, रोहतक एवं हिसार के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करना।

43. राज्य सरकार सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करने व रावी– ब्यास का हरियाणा के वैध हिस्से का पानी लेने के लिए कृतसंकल्प है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम–2004 के विरूद्ध चिरलम्बित राष्ट्रपति के संदर्भ पर नियमित सुनवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 2.5 करोड़ से अधिक लोगों के प्रतिनिधि के रूप में इस सदन ने सतलुज–यमुना लिंक नहर को शीघ्र पूरा करवाने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश की नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे हरियाणा की प्यासी धरती तक पानी पहुंचाया जा सकेगा।

44. मैं, सिंचाई एवं जल संसाधनों के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 के 2162.87 करोड़ रुपये की तुलना में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2016–17 के लिए 2621.92 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

पशुपालन एवं मत्स्य

45. प्रदेश में गौवध और गौमांस की बिक्री का निषेध करने वाले गौवंश सरंक्षण व गौ–संवर्धन अधिनियम, 2015 को अधिसूचित करना इस गरिमामय सदन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 309 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अखिल भारतीय औसत दुग्ध उपलब्धता की तुलना में 805 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता के साथ हरियाणा देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

46. 'देसां मैं देस हरियाणा, जित दूध दही का खाणा' को सार्थक रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने ''मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन'' योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सबसिडी को अप्रैल, 2015 से चार रुपये प्रति लिटर से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लिटर करने का एक अत्यंत प्रगतिशील निर्णय लिया है। इसके लिए मैं 24.50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

47. मैं, पशु चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 58.48 करोड़ रुपये के आबंटन के अतिरिक्त पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के लिए 40 करोड़ रुपये के योजनागत आबंटन का प्रस्ताव भी करता हूँ।

48. पशुपालन और डेरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं राज्य के हिस्से सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत संशोधित अनुमान 2015–16 के 162.47 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2016–17 में 221.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ जोकि 36.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

49. मैं, मत्स्य पालन के विकास के लिए 17.65 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 से 14 प्रतिशत अधिक है।

सहकारिता – चीनी मिलों को सहायता

50. गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार देश में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दे रही है। बाजार में चीनी के थोक एवं उपभोक्ता मूल्य कम होने से जहां उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, वहीं चीनी मिलों, चाहे वे सहकारी क्षेत्र की हों या निजी क्षेत्र की हों, को चीनी के इस कम मूल्य के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों को अदायगी समय पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान इन चीनी मिलों को ऋण प्रदान करने का एक साहसिक कदम उठाया है। सहकारी चीनी मिलों के लिए वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों में 646 करोड़ रुपये का काफी अधिक बढ़ा हुआ आबंटन किया गया। इसी प्रकार, निजी चीनी मिलों को ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 में 187 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।

51. मैं, गन्ना किसानों की सहायता के लिए 2016–17 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को ऋण प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की सहायता के लिए 50 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ। सहकारिता के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए, मैं 717.61 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

वन एवं वन्य जीव

52. वनों के विकास के लिए, सामुदायिक व कृषि भूमि पर वनीकरण के विकास, बेकार भूमि पर वनीकरण एवं कृषि वनीकरण, सिविल वनों सहित अवक्रमित वनों का सुधार और शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टिका के विकास के लिए अधिक आबंटन का प्रस्ताव है। वाटरशैड आधार पर मृदा एवं पानी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र में जल संरक्षण ढांचों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 16.60 करोड़ रुपये की राशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं समेकित वन्य जीव प्राकृतिक निवास विकास की केन्द्रीय योजना के तहत राज्य के हिस्से सहित 2. 5 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित कर रहा हूँ। वन्य जीव संरक्षण का कुल आबंटन, बजट अनुमान 2015–16 के आबंटन से 29.3 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है।

खाद्य एवं आपूर्ति

53. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 132.35 लाख लाभानुभोगियों को लाया गया है। इस योजना के तहत हेरा–फेरी को रोकने के लिए लाभानुभोगियों से लेकर पणधारकों तक की समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं तक वितरण ऑनलाइन हो जाएगा।

[कैप्टन अभिमन्यु]

54. मैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए 2016–17 में 188 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

पंचायतें एवं ग्रामीण विकास

55. हरियाणा सरकार के पंचायती राज संस्थाओं को प्रबुद्ध शिक्षित नेतृत्व देने के ऐतिहासिक कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया और अपने फैसले में कहा है कि हरियाणा सरकार का यह कदम देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मार्गदर्शक है। महिला प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या, ''स्वच्छ भारत–स्वच्छ हरियाणा'' अभियान के प्रति गहन चेतना और ग्राम सचिवालय की पहल से पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर दक्ष और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए हरियाणा अग्रणी स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मैं, ग्रामीण विकास, समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, भू–अभिलेख सामुदायिक विकास एवं पंचायतों के लिए 2016–17 में 2824.47 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इसे हरियाणा ग्रामीण विकास कोष द्वारा अपने 516.56 करोड़ रुपये के संभावित व्यय के साथ अनुपूरित किया जाएगा।

56. मैं, राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के हिस्से सहित 330 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। इससे प्रतिदिन 251 रुपये की देशभर में सर्वाधिक मजदूरी देने और 74.40 लाख मानव दिवस सृजित करने का प्रस्ताव है।

57. मैं, समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए राज्य के हिस्से सहित 100 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आबंटन का प्रस्ताव भी करता हूँ। मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविक मिशन के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य प्रकल्पों के अलावा, मैं ''सबके लिए आवास'' योजना के तहत 150 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

58. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, मैं बजट अनुमान 2016–17 में 473.80 करोड़ रुपये का तथा पंचायतों के लिए 735.86 करोड़ रुपये का आबंटन करता हूँ। ग्राम सचिवालयों सहित कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये आबंटित करने के अतिरिक्त हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के लिए 82 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) की केन्द्रीय योजना के तहत, मैं राज्य के हिस्से सहित 125 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत आबंटन को 55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान और वैट पर अधिभार 543.86 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

59. मेवात एवं शिवालिक क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत सरकार की नीति, संबंधित विभागों के बजट शीर्ष के तहत इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट

योजनाएं शामिल करने की है। उदाहरण के तौर पर मेवात क्षेत्र में कोटला झील तथा संबंधित सिंचाई योजनाओं और शिवालिक क्षेत्र में वाटरशैड क्षेत्रों का विकास सिंचाई विभाग तथा वन विभाग के लिए आबंटित धनराशि के जरिये किया जाएगा। वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम के लिए मैं 49.10 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

उद्योग एवं खान

60. राज्य ने अपनी पहली ''हैपनिंग हरियाणा'' ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया। यह रिकॉर्ड की बात है कि इस समिट के दौरान 5.84 लाख करोड़ रुपये के 359 समझौते किए गए।

61. राज्य ने अपनी नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015 लागू की है। यह नीति सार्वजनिक और निजी निवेश के सम्मिश्रण के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। यह नीति बड़े पैमाने पर रोजगार–सृजन के लिए एम.एस.एम.ई. एवं कौशल विकास पर बल देते हुए कारोबार करने, नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल एवं लागत प्रभावी माहौल उपलब्ध करवाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ–साथ हरियाणा को सामाजिक व आर्थिक विकास के उच्च प्रक्षेप–पथ पर लेकर जाएगी।

62. इस नीति की परिकल्पना, कारोबार करने की सहुलियत, उद्योगों के भौगोलिक विस्तार, नए उद्यमों की स्थापना के लिए एक ही छत के नीचे ऑनलाइन स्वीकृतियां और उद्योगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के शीघ्र समाधान के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के अपने चार प्रमुख सिद्धातों के साथ, कारोबार की सहुलियत और कारोबार की लागत कम करके हरियाणा को एक पंसदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और ''मेक इन इंडिया'' पहल के साथ मिलकर यह नीति उद्योगों के भौगोलिक प्रसार के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास और कलस्टर विकास के माध्यम से एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और विनिर्माण पद्धतियों में ''ज़ीरो डिफैक्ट, ज़ीरो इफैक्ट'' को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने और रोजगार सृजित करने के लिए हम खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

63. महोदय, हम सभी जानते हैं कि अकेले सरकारी नौकरियां ही समाज से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार हर वर्ष कुछ हजार नौकरियां ही प्रदान कर सकती है, जबकि हर वर्ष नये 5 लाख युवाओं को लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। अतः योजनाकारों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना या व्यापार एवं उद्योग में स्व–रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अनिवार्य हो गया है।

64. महोदय, यह गरिमामय सदन इस तथ्य की सराहना करेगा कि हरियाणा के सभी युवाओं के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है, कृषि के प्रतिफल को सुधारने के साथ–साथ विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का उच्च विकास सुनिश्चित किया जाए।

65. उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 में, हमने अपने पारम्परिक उद्योगों को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करने, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने,

[कैप्टन अभिमन्यु]

हरियाणा के युवाओं को उनके घरों के निकट ही रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने और छोटी सहायक विनिर्माण इकाइयों के नए स्रोत सृजित करने में सक्षम बनने के लिए रक्षा, रेलवे, उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में कुछ नए बड़े मुख्य उद्योग लाने की परिकल्पना की है। हमने सेवा क्षेत्र के विकास पर विशेष बल देने का भी प्रस्ताव किया है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने और प्रदेश में राजस्व सृजित करने की अपार क्षमता है। नई नीति में उद्यमियों, पहली पीढ़ी के उद्यमियों और स्टार्टअप द्वारा रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

66. सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियां बहाल की हैं। सरकार ने कानूनी एवं प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद, नदी में रेत और पत्थर की खनन गतिविधियों को फिर से खोला है। इससे निर्माण लागत कम हुई है, जिसका रियल एस्टेट क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इससे जनता को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है और राज्य के लिए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। रॉयल्टी एवं करों के संग्रहण को सरल बनाने और कर चोरी कम करने के लिए, विभाग ''ई–रवाना'' शुरू करेगा और जिला खनिज कोष क्रियान्वित करेगा।

67. मैं, उद्योग एवं खनिज के लिए बजट अनुमान 2016–17 में 828.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 194.98 करोड़ रुपये से 325.1 प्रतिशत अधिक है।

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

68. प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का उद्देश्य उसे एक उत्तरदायी नागरिक और विवेकशील मानव बनाना है, जोकि स्वयं के लिए एक लाभदायक रोजगार प्राप्त करने के लिए समुचित रूप से दक्ष हो और राज्य और राष्ट्र के लिए उत्पादक तरीके से योगदान दे।

69. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के उपरांत, राज्य ने स्कूलों तक विद्यार्थियों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काफी सुधार किया है। पहुंच ने तो स्कूलों को बच्चों के समीप ला दिया, लेकिन यह शिक्षा की गुणवत्ता ही है, जो बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति को प्रबल बनाती है। इस आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

70. ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार माध्यमिक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने 490 सरकारी स्कूलों में 10 व्यावसायिक ट्रेड्स शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के रोजगारपरक कौशल को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल किया गया है।

71. राज्य सरकार ''सर्वशिक्षा अभियान'' और ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' नामक

दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। क्रियान्वित किए जा रहे अन्य मुख्य कार्यक्रमों में बालिकाओं का अस्तित्व, संरक्षण, कल्याण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ''बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'' कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ''पढ़े भारत, बढ़े भारत'' ''हरियाणा एक खोज'' और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ''कला उत्सव'' शामिल हैं।

72. मैं, सर्वशिक्षा अभियान के लिए 2016–17 में 786 करोड़ रुपये के परिव्यय का आबंटन करता हूँ, जो कि संशोधित अनुमान 2015–16 के 655 करोड़ रुपये के परिव्यय से 20 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, मैं संशोधित अनुमान 2015–16 के 269.53 करोड़ रुपये की तुलना में 537.98 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 99.2 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार, ड्यूल डैस्क स्कीम के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 के 35 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 2016–17 में 110 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जो 214.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

73. वर्ष 2015–16 में पांच नए राजकीय महाविद्यालयों अर्थात् राजकीय महाविद्यालय, भूना (फतेहाबाद), राजकीय महिला महाविद्यालय, पुन्हाना (मेवात), राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी गुजरान(फरीदाबाद), राजकीय महिला महाविद्यालय, अटेली (महेंद्रगढ़) तथा राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरसा स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, सरकार ने अलेवा, मानेसर, उकलाना, गुहला चीका, शहजादपुर, उगालन, कुरुक्षेत्र, कुरथला, कनीना, जुण्डला, सोनीपत, छिलरो, कालांवाली, मोहना, रानिया, इत्यादि में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

74. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जो उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए, मैं बजट अनुमान 2015–16 के 15.25 करोड़ रुपये के परिव्यय में 988.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2016–17 में 166 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। नए महाविद्यालय खोलने के लिए, मैं बजट अनुमान 2016–17 में 110 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन कर रहा हूँ। उच्चतर शिक्षा के लिए, मैं 2016–17 में 1649.52 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 1457.84 करोड़ रुपये की तुलना में 13.15 प्रतिशत अधिक है।

75. वर्ष 2015–16 के 10,833 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के समक्ष, मैं बजट अनुमान 2016–17 में शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) के लिए 13,043.84 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 20.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा

76. जैसाकि हम सभी जानते हैं शिक्षा बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए रामबाण है और हम शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल बदलाव ला रहे हैं, ताकि हरेक का लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास हो।

[कैप्टन अभिमन्यु]

77. राज्य सरकार ने युवाओं को हरियाणा के आर्थिक तथा चहुंमुखी विकास में भागीदार बनाने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल विकास मिशन (एच.एस.डी.एम.) का गठन किया है। कई योजनाएं अर्थात, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए ''सूर्य'' (युवाओं की स्किलिंग, अप–स्किलिंग, री–स्किलिंग तथा असेसमेंट), अन्य विभागों की कौशल पहलों के तहत युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए ''दक्ष'' (हरियाणा में अनुप्रयुक्त ज्ञान तथा कौशल का प्रसार), हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा उद्योगों की आवश्यकता अनुसार उनकी अपेक्षित मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सीखो–सिखाओ कार्यक्रम ''स्मार्ट'' (स्किल मार्ट) शुरू किया जाना प्रस्तावित है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत हर वर्ष लगभग 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। संशोधित अनुमान 2015–16 के 9.00 करोड़ रुपये की तुलना में हरियाणा कौशल विकास मिशन के लिए 2016–17 में 25.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 2016–17 में नीलोखेड़ी, करनाल में एक नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। मैं बजट अनुमान 2016–17 में तकनीकी शिक्षा के लिए 501.42 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

औद्योगिक प्रशिक्षण

78. 2015–16 में 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भकलाना (हिसार), सूरेवाला (हिसार), शाहबाजपुर(महेन्द्रगढ़), मतलौडा (पानीपत), छछरौली(यमुनानगर), तलवाड़ा (फतेहाबाद), बापोली (पानीपत), भोजावास (महेन्द्रगढ़), इंद्री (करनाल) और सिकरोना (फरीदाबाद) में 10 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा राखी शाहपुर (हिसार) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

79. मैं संशोधित अनुमान 2015–16 के 359.02 करोड़ रुपये के समक्ष 2016–17 में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 413.81 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, यह 15.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

खेल

80. प्रदेश में हरियाणा खेल और शारीरिक तंदुरूस्ती नीति, 2015 लागू की जा रही है। इस नीति के तहत, 2015–16 में एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों के 89 पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कारों के रूप में 50.65 करोड़ रुपये तथा 71 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 2.32 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, केरल में आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलों के 236 पदक विजेताओं को 8.69 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा, 22 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को भी 81.50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये। नकद पुरस्कारों के अलावा, प्रोत्साहन के रूप में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की जा रही हैं।

81. मैं 2015–16 के 245.20 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के समक्ष बजट अनुमान 2016–17 में 293.53 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्वास्थ्य

82. राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, 58 अस्पतालों, 119 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 485 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2630 उप–केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सफीदों (जींद) का उन्नयन 50 बिस्तर के अस्पताल के रूप में तथा 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में किया गया। वर्ष 2015–16 में 10 नए अस्पताल भवनों, 12 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।

83. मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (एम.एम.आई.वी.) के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में द्वितीय स्तरीय सर्जरियां निःशुल्क की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 73 निःशुल्क मूलभूत प्रयोगशाला जांच, एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड और ई.सी.जी. मुफ्त रेफरल परिवहन, इनडोर उपचार सेवाओं और 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ 231 विभिन्न प्रकार के ऑप्रेशन किये जा रहे हैं।

84. अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली, ई–उपचार सेवा नागरिक अस्पताल पंचकूला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर रानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरवाला और बी.पी.एस. मैडिकल कॉलेज, खानपुरकलां में शुरू की गई है। इस सेवा के अन्तर्गत मरीज को एक अनन्य पहचान नम्बर दिया जाएगा। इस प्रणाली के विभिन्न भाग हैं जैसेकि रोगी पंजीकरण, इलैक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रिकार्ड, और अन्य सहायक इकाइयां। हमारा इस सेवा का वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्त तक सभी जिला हस्पतालों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

85. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, जोकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) कम होकर 33 (एन.एफ.एच.एस.–4, 2015–16) तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) कम होकर 127 रह गई है। इसी प्रकार, नवम्बर 2015 में संस्थागत प्रसूतियां बढ़कर 89.10 प्रतिशत हो गई है। कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 3.0 (एस.आर.एस. 2002) से कम होकर 2.1 (एम.एफ.एच.एस.–4, 2015–16) हो गई है। राज्य में 375 एंबुलेंस (48–एडवांस लाइफ सपोर्ट, 259 बेसिक लाइफ सपोर्ट, 34 रोगी परिवहन एंबुलेंस और 34 किलकारी–बैकहोम) हैं।

86. सरकार ने कुटैल, जिला करनाल में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय; गांव बाढसा, जिला झज्जर में भारत सरकार का नेशनल कारडियो वेस्कुलर इंस्टिच्यूट, गांव मानेठी, जिला रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स); पंचकूला, भिवानी तथा जींद में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करवाने का निर्णय लिया है। सरकार राज्य के हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहती है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

87. आयुष विभाग, जनसाधारण को आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, 3 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 यूनानी अस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 458 आयुर्वेदिक औषधालय, 18 यूनानी औषधालय, 20 होम्योपैथिक औषधालय और पंचकूला में एक भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान प्रणाली संस्थान (आई.आई.एस.एम.एंड आर.) कार्यरत हैं। सरकार एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक आयुष का प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

88. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2016–17 में 3916.94 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 2,857.28 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 37.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

89. माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय– 'अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान' के सिद्धान्त के अनुरूप उनके सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

90. मैं अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट अनुमान 2015–16 के 133.94 करोड़ रुपये की तुलना में 108.3 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ 2016–17 में 279 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का आबंटन करता हूँ। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों/टपरीवास जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली समाज के सभी वर्गों की विधवाओं की अनुदान राशि 31,000 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त, 2.5 एकड़ भूमि जोत या एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले सभी परिवारों को दी जा रही 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 11,000 रुपये किया गया है। सभी पात्र महिला खिलाड़ियों को 31,000 रुपये देने का भी निर्णय लिया गया है।

91. 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना' के तहत समाज में जाति चेतना कम करने के उद्देश्य से दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,01,000 रुपये की गई है।

92. सरकार ने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने, सरकार द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों और कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की है।

93. वर्ष 2016–17 के लिए, मैं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 671.62 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि बजट अनुमान 2015–16 के 366.72 करोड़ रुपये के आबंटन से 83 प्रतिशत अधिक है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

94. सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किन्नर व बौना भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाओं की राशि पहली जनवरी, 2016 से 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 2019 तक हर साल 1 जनवरी को इसमें 200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी और पहली जनवरी, 2019 को यह राशि 2000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत–प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है।

95. सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए, मैं 2016–17 में 4210.38 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 3618.71 करोड़ रुपये की तुलना में 16.4 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास

96. महिला एवं बाल कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की प्रमुख योजनाओं में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'आपकी बेटी हमारी बेटी', 'पूरक पोषण कार्यक्रम', 'समेकित बाल विकास सेवाएं योजना', आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा महिलाओं के लिए एकल केन्द्र 'सखी' शामिल हैं। सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित किये गये हैं।

97. वर्ष 2015 में लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2016 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार–2015 से सम्मानित किया गया। पिछले 10 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 900 के आंकड़े को पार कर गया है।

98. महिला एवं बाल विकास के लिए, मैं 2016–17 में 1207.84 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 982.53 करोड़ रुपये की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

जिला योजना

99. मैं संशोधित अनुमान 2015–16 के 211.48 करोड़ रुपये की तुलना में 2016–17 में 400 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इससे जिला प्रशासन को जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

गृह, कारागार तथा न्याय प्रशासन

100. 2015–16 के दौरान, फोरेंसिक मामलों का समय पर निपटान करने के लिए भोंडसी (गुड़गांव), सुनारिया (रोहतक), मोगीनंद (पंचकूला) और हिसार में 4 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से भोंडसी और सुनारिया में दो क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएं चालू हो गई हैं। प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से 'सड़क सुरक्षा पर व्यय' की एक नई योजना बनाई गई है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

101. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गृह विभाग हेतु 3768.54 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 3093.33 करोड़ रुपये से 21.8 प्रतिशत अधिक है। कारागार तथा न्याय प्रशासन के लिए, मैं 2016–17 के योजनागत परिव्यय में 1015.03 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 में 894.63 करोड़ रुपये है।

सड़क, परिवहन तथा मेट्रो

102. हम हरियाणा के लिए 906 किलोमीटर लम्बे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा इस्टर्न पेरिफरल एक्स प्रैस–वे का निर्माण शुरू करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार के आग्रह पर इस वर्ष भारत सरकार प्रदेश में नई सड़कों– (1) गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी, (2) एनएच–148 बी पर फतेहाबाद– रतिया–बुढलाडा मंडी, (3) जींद–सफीदों–पानीपत, (4) तितरम मोड़–कैथल– जींद–हांसी और (5) हिसार–तोशाम–बाढडा–सतनाली–महेन्दगढ़–रेवाड़ी को नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर सहमत हुई है, जिन्हें चार मार्गी बनाया जाएगा।

103. हरियाणा राज्य सड़क विकास निगम ने प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) की सहायताप्राप्त योजनाओं के अंतर्गत सड़क और पुलों के कार्यों पर 158.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। वर्ष 2016–17 के लिए, 1979 करोड़ रुपये लागत की 10 परियोजनाएं वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के समक्ष रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, 1064 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 395 किलोमीटर लंबाई की रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, नारनौल और सोनीपत की विभिन्न सड़क परियोजनाएं वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है।

104. सरकार ने पहली बार, राज्य के बजट के तहत वर्ष 2015–16 के लिए केवल विभिन्न राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों तथा अन्य जिला सड़कों (ग्रामीण सड़कों) की मरम्मत के लिए मई, 2015 में 1560 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। अधिकांश कार्य प्रगति पर हैं और मई, 2016 के अंत तक पूरे हो जाएंगे। शेष सड़कों की मरम्मत और सुधार का कार्य वर्ष 2016–17 के दौरान करवाया जाएगा। वर्ष 2015–16 के दौरान, 250 किलोमीटर सड़कें 3.66 से 5.50 मीटर तक चौड़ी की गईं। वर्ष 2016–17 में गांव से गुजरने वाली 1250 किलोमीटर लम्बी सड़कें 3.66 से 5.50 मीटर तक चौड़ी की जानी प्रस्तावित हैं।

105. सोनीपत–जींद रेल लाइन शीघ्र शुरू होने वाली है। रोहतक–महम–हांसी के बीच रेल लाइनें बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु इस वर्ष समुचित राशि उपलब्ध करवाई गई है।

106. मैं लोक निर्माण(भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 2015–16 के 1925 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के समक्ष बजट अनुमान 2016–17 में 2,948 करोड़ रुपये के

योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 53.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस परिव्यय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों तथा पुलों के निर्माण, चौड़ा करने तथा उन्नयन के लिए 1,238.55 करोड़ रुपये शामिल है।

परिवहन

107. प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुधार के लिए हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने की मशीनों के कार्यान्वयन, आरएफआईडी पासिज़ तथा बसों में जीपीएस प्रणाली की स्थापना जैसे अनेक नये कदम उठाए गये हैं। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए निजी–सार्वजनिक भागीदारी पद्धति पर बस अड्डों/ टर्मिनलों का विकास और उपलब्ध बस बेड़े का अधिकतम उपयोग कुछ ऐसे उपाय हैं, जिनके फलस्वरूप विभाग प्रथम चरण में घाटे से उबर जाएगा। इसके अलावा, 600 नई बसें शीघ्र ही कुल बस बेड़े में शामिल किये जाने की संभावना है।

108. परिवहन विभाग के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 के 2038.65 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 2016–17 के लिए 2464.42 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जोकि 20.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मेट्रो परियोजना के लिए, 2015–16 के 226. 18 करोड़ रुपये के सम्भावित खर्च के समक्ष वर्ष 2016–17 के लिए 289.42 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा

109. सरकार का संकल्प सभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति करने का है। सरकार ने 2015 में 'म्हारा गांव–जगमग गांव' नामक एक अभिनव योजना शुरू की है। इस योजना के आरम्भ में 297 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 15 घंटे तथा बाद में 25 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 18 घंटे प्रतिदिन की गई है। इसके बेहतरीन परिणामों से उत्साहित होकर, चालू वर्ष में इस योजना का विस्तार 260 फीडरों तक करने का निर्णय लिया गया है, जिसके पश्चात लगभग 1000 गांवों को प्रतिदिन 15 घंटे की बढ़ी हुई बिजली आपूर्ति होगी।

110. जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण के आरम्भ में कहा है कि हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय तथा डिस्कॉम्स के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की बिजली वितरण कम्पनियों के प्रचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के लिए हर पक्ष के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक घाटे को 2014–15 के 29.58 प्रतिशत से 2018–19 में 15 प्रतिशत करने के उद्देश्य से अपनी दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रत्येक गतिविधि के लिए बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा विशिष्ट लक्षित कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

111. शहरी क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। गुड़गांव में स्मार्ट बिजली ग्रिड स्थापित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। यह गुड़गांव शहर तथा साथ लगते औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की एक अनूठी परियोजना होगी, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करेगी। इस योजना के प्रथम चरण की लागत

[कैप्टन अभिमन्यु]

लगभग 1200 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के लिए, केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय से 300 करोड़ रुपये का अनुदान मिलने की संभावना है।

112. 8 मार्च, 2016 को घोषित सौर ऊर्जा नीति, 2016 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा विभाग अक्षय ऊर्जा दायित्वों (आर.पी.ओ.) के लक्ष्य के अलावा 200 मैगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए छत पर स्थापित होने वाले संयंत्रों को प्रोत्साहित करने व 1–2 मैगावाट के भूमि पर स्थापित होने वाले सौर संयंत्रों को 2 प्रतिशत खरीद मूल्य में वरीयता देने की योजना पर कार्य कर रहा है।

113. मैं 2016–17 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 16,826.70 करोड़ रुपये का आबंटन करता हूँ, जिसमें 10,018.73 करोड़ रुपये का योजनागत तथा 6807.97 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत बजट शामिल है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

114. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में बेहतर, दक्ष और नियंत्रित ढंग से सीवरेज और बरसाती पानी की प्रणालियां उपलब्ध करवाने और उनके रख–रखाव के लिए राज्य सरकार का इरादा पेयजल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम बनाने का है। इससे वितरण प्रणाली में अवैध ढंग से छेड़छाड़ पर अंकुश लगेगा और अंततः गांवों व शहरों के सभी भागों में समान रूप से पानी की आपूर्ति होगी।

115. सीवेज के उचित उपचार और निपटान के लिए उन सभी कस्बों या क्षेत्रों में सीवेज उपचार संयंत्र बनाये जाने की आवश्यकता है, जहां सीवरेज प्रणाली है। वर्तमान में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पालिका कस्बों में 78 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए गए हैं, 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और आगामी दो वर्षों के दौरान 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी है।

116. शहरी क्षेत्रों की अनाधिकृत कॉलोनियों में पब्लिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। केवल अनाधिकृत कॉलोनियों की मांग को पूरा करने के लिए रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) संयंत्र स्थापित करने की एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और विपणन सहित शेष आधारभूत संरचना के कार्य निजी भागीदार द्वारा किए जाएंगे। मैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 के 2649.38 करोड़ रुपये की तुलना में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2016–17 के लिए 3108.37 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

शहरी विकास

117. रियल एस्टेट विनियामक अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, रियल एस्टेट में लेन–देन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने और आवास परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने में बड़ा सहायक होगा।

118. राज्य के निम्न एवं मध्यम क्षमता वाले कस्बों में 5 से 15 एकड़ परियोजना आकार के साथ प्रति एकड़ 240 से 400 व्यक्तियों के घनत्व वाली उच्च घनत्व और 65 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र की प्लॉटेड कॉलोनियां विकसित करने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन कॉलोनियों में उदार नीति तंत्र से छोटे प्लाट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे शहरों में ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए डेवलेपर्स को आकर्षित करने हेतु एक ओर जहां लाइसेंस शुल्क और बाह्य विकास शुल्क की दरें काफी हद तक कम की गई हैं, वहीं दूसरी ओर परिवर्तन शुल्क एवं आंतरिक विकास शुल्क समाप्त कर दिया गया है। यह नीति, जहां एक ओर अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाएगी, वहीं दूसरी ओर ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव बनाएगी।

119. उदार और पारदर्शी समेकित लाइसेसिंग नीति(एनआईएलपी) से रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के नये द्वार खुलेंगे, जिससे सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ते मकान उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा। सरकार ने छोटे भू–मालिकों को आधारभूत संरचना विकास में भागीदार बनाने के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की प्रक्रिया अपनाई है। सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलेपमेंट नीति घोषित की है, जिसमें जनसंख्या की सघनता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैट्रो मार्गों के साथ–साथ उन्नत बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रावधान है।

120. दो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, ''अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत)'' और ''स्वच्छ हरियाणा–स्वच्छ भारत'', शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मैं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 3549.11 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2889.14 करोड़ रुपये की तुलना में 22.8 प्रतिशत अधिक है।

ई–प्रशासन

121. ''सरकार कम से कम–सुशासन अधिकतम'' के सिद्धान्त के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रक्रिया सुधार और आईटी आधारित सरकारी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सुशासन पर अतुलनीय बल दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव हस्तक्षेप को कम करके और बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी स्तरों पर परेशानियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।

122. राज्य ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए ''सीएम विंडो'' वैब पोर्टल, सम्पत्ति के पंजीकरण के लिए ई–अपॉइंटमेंट, समेकित वित्त प्रबंधन प्रणाली, हरियाणा पुलिस का नागरिक पोर्टल ''हर समय'' और आधार एवं भू–अभिलेख को जोड़ने जैसी अनेक ई–शासन पहलों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। हरियाणा समेकित जन्म पंजीकरण प्रणाली विकसित और क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है, जिससे नवजात बच्चे का आधार नामांकन और जन्म पंजीकरण होता है।

123. कराधान के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने ई–पंजीकरण, कर की ई–अदायगी एवं रिटर्न की ई–फाइलिंग, ई–निविदा एवं सी–फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

सरकार ने राज्य में शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के लिए ई–परमिट एवं ई–पास प्रणाली शुरू की है।

124. डिजिटल हरियाणा पहल के तहत, 2 मई, 2015 को स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की 22 सेवाएं शुरू की गईं और ये सेवाएं सांझा सेवा केन्द्रों, ई–दिशा केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नगरपालिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन विधि में प्रदेशभर में सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही हैं। दूसरे चरण में, नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी 20 प्रमुख विभागों की कुल 105 ई–सेवाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा में कुल 2337 सांझा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए समेकित वित्त प्रबंधन प्रणाली के लिए वैब पोर्टल, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण कार्यक्रम, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पोर्टल (म्हारी पंचायत), स्कूल के लिए एमआईएस और राजस्व अदालती मामले निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

125. हरियाणा की ई–शासन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। राज्य श्रेणी के तहत, हरियाणा को 19 सितम्बर, 2015 को प्रतिष्ठित स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड–2015 और 3 दिसम्बर, 2015 को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सीएसआई–निहिलेंट अवार्ड्स 2015 से सम्मानित किया गया। हरियाणा ने डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान तीन जिलों के उत्कृष्ट योगदान के लिए 28 दिसम्बर, 2015 को डिजिटल इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया।

126. मैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए बजट अनुसार 2016–17 के लिए 85 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 2015–16 में 43 करोड़ रुपये के आबंटन से लगभग दोगुना है। इसके अतिरिक्त, मैं बजट अनुमान 2016–17 में विभिन्न विभागों की योजनागत स्कीमों में सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेंस/कम्प्यूटरीकरण के लिए 225 करोड़ रुपये का आबंटन करता हूँ।

पर्यटन और संस्कृति

127. कुरुक्षेत्र वह धरा है, जहां महाभारत के महायुद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत संदेश दिया था और यह हमारी पर्यटन विकास योजना के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना का विकास करने और इसे विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए इस शहर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कृष्ण सर्किट में शामिल किया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने विकास के लिए कुरुक्षेत्र शहर सहित पांच महत्त्वपूर्ण स्थलों नामतः सन्निहित सरोवर, अमीन कुण्ड, नरकातारी, ब्रह्मसरोवर एवं ज्योतिसर की पहचान और चयन किया है। इन अभिनव परियोजनाओं में श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत के विभिन्न विषयों पर आधारित एक थ्री डी मल्टीमीडिया शो, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की स्थापना और महाभारत युद्ध के 48 कोस के वास्तविक क्षेत्र को दर्शाने वाले थीम पार्क कॉम्पलैक्स को शामिल किया गया है। तदनुसार, 99 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थलों के विकास की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई है।

128. हरियाणा सरकार ने वैदिक साहित्य में वर्णित क्षेत्रों और प्रदेश में भूमि के नीचे बह रही पावन सरस्वती नदी की खोज के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसके सदस्यों के रूप शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने सिंधु दर्शन एवं कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है।

129. मैं इन परियोजनाओं हेतु पर्यटन के लिए 2016–17 में 66.81 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2015–16 के 31.90 करोड़ रुपये से 109.4 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय समावेशन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

130. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, 18 दिसम्बर, 2014 तक सभी 48.58 लाख परिवारों के बैंक खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला हरियाणा भारत का चौथा राज्य है। 15 जनवरी, 2016 तक 52.6 लाख बैंक खाते खोले गये हैं और इनमें 1,112 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इन खातों का उपयोग छात्रवृत्तियां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अनेक अन्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए किया जा रहा है।

131. माननीय मुख्यमंत्री ने हमें कल्याणकारी योजनाओं के तहत बिचौलियों के बिना लाभार्थी को निधि का सीधा प्रवाह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा हैं। सरकार ने 73 कल्याणकारी योजनाओं की पहचान की है, जिनमें डीबीटी के तहत लाभ दिए जा सकते हैं। सरकार को सितम्बर, 2016 तक इन कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभानुभोगियों को डीबीटी के तहत लाये जाने की उम्मीद है और वर्ष 2016 के अंत तक यह सुविधा उनके मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे ''जैम''(जनधन, आधार और मोबाइल फोन) की त्रिमूर्ति पूरी हो जाएगी। डीबीटी योजनाओं की सूची बजट दस्तावेज में दी गई है।

नई अवसंरचना विकास पहलें

रेलवे

132. राज्य सरकार द्वारा चिह्नित रेलवे परियोजनाओं के विकास, वित्तपोषण एवं क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन करने हेतु रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता किए जाने की संभावना है। अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने से राज्य में रेलवे तंत्र का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इससे सुरक्षित एवं किफायती यात्रा और माल की ढुलाई की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

नागरिक विमानन

133. हवाई सम्पर्क किसी भी राज्य के विकास का पैमाना है। हरियाणा में करनाल, हिसार, नारनौल, भिवानी और पिंजौर में पांच एयरोड्रोम हैं। लेकिन यह चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी राज्य की मुख्य धरा पर कोई चालू घरेलू हवाई अड्डा

[कैप्टन अभिमन्यु]

स्थापित नहीं किया जा सका है। इसके मद्देनजर, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार सिविल एयरोड्रोम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की है। प्रथम चरण में, सरकार की 50 करोड़ रुपये की लागत से रनवे को 4000 फुट से बढ़ाकर 7000 फुट करने और टर्मिनल भवन के नवीनीकरण की योजना है।

134. हिसार सिविल एयरोड्रोम को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति–प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता की रिपोर्ट के आधार पर, हिसार सिविल एयरोड्रोम को सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई हवाई अड्डा, रख–रखाव, मरम्मत एवं ओवरहालिंग हब के रूप में विकसित करने के संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी। करनाल सिविल एयरोड्रोम का उन्नयन घरेलू हवाई अड्डे के रूप में करने का भी प्रस्ताव है।

135. अतः मैं, 2016–17 के लिए 89.81 करोड़ रुपये के बजट आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि 2015–16 में 20.52 करोड़ रुपये था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब वर्ष 2016–17 के लिए अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

136. महोदय, वित्त वर्ष 2016–17 के इन बजट अनुमानों में मेरा नये करों का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर, मैं कुछ कर छूट देना चाहूंगा, जिनका राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

- जूता उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 500 रुपये और इससे अधिक के एमआरपी वाले जूतों पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और जूतों के ऊपर के हिस्से को वैट से छूट देने का प्रस्ताव है। इससे प्रदेश में और अधिक जूता उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं राज्य में निर्मित 'खल', 'बिनौला', 'बेसन' तथा 'सूती धागे' को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं विनिर्माण के लिए राज्य के कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 'सेवियां' पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- स्वच्छ पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इलैक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- राज्य में परिवारों को राहत प्रदान करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं रसोई में पत्तेदार सब्जियों को काटने के काम लाए जाने वाले 'छोटा टोका' पर कर की अदायगी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- मैं, राज्य के प्रभावित पंजीकृत डीलर्स, जिनका फरवरी, 2016 के आरक्षण आंदोलन के दौरान माल चोरी या नष्ट हो गया था, को कर, ब्याज, जुर्माना तथा अन्य अदायगियों के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए एक माफी योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- ग्राहकों को खरीदे गए माल का बिल या इनवायस लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ''बिल दो, पुरस्कार जीतो योजना'' शुरू करने का प्रस्ताव करती है। इससे विक्रेता एवं डीलर बड़े पैमाने पर इसका अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसके फलस्वरूप कर चोरी रोकते हुए सरकारी खजाने में अधिक राजस्व आएगा।

137. महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए क्षेत्रवार आबंटनों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। मैं कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (सिंचाई, सहकारिता एवं ग्रामीण विद्युतीकरण सबसिडी सहित) के लिए वर्ष 2016–17 में 13494 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ। ग्रामीण विकास एवं पंचायत को 2824.47 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। शिक्षा क्षेत्र (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति) को 14,305.34 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 3916.94 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। उद्योग एवं खनिज विकास के लिए 828.80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समाज कल्याण, पोषाहार तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए 6189.87 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। बिजली क्षेत्र के लिए 16,826.70 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3108.37 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 3645.86 करोड़ रुपये और जिला योजना के लिए 400 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है। परिवहन क्षेत्र के लिए 2464 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है। भवनों और सड़क क्षेत्र के लिए 4485.11 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

138. कोई भी प्रयास तब तक सार्थक नहीं होता, जब तक कि उससे समाज के वंचित वर्ग लाभान्वित न हों। मैंने वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति उप योजना घटक के तहत अनुसूचति जातियों के कल्याणार्थ विशेष तौर पर 6373.48 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया है, जोकि कुल योजनागत परिव्यय का 20.3 प्रतिशत है।

139. महोदय, यह बजट प्रस्ताव ''सबका साथ–सबका विकास'' के सिद्धान्त पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है। बजट में कृषि एवं उद्यम क्षेत्रों में रोज़गार के और अधिक अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है। इसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के दबाव को कम करने और निजी क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों को विशेष महत्त्व दिया गया है ताकि राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और जनसांख्यिकीय लाभ उठाया जा सके। यह पूंजीगत व्यय और अवसंरचना विकास पर विशेष बल देता है। इसमें युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। यह सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के बीच असमानता को दुरुस्त करता है। यह कल्याणकारी राज्य की हमारी वचनबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक क्षेत्र पर और अधिक बल देता है। मैं इस सम्मानित सदन से, राजनैतिक एवं वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर इस पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने और इस प्रस्ताव को अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ। मैं, एक विकसित और प्रगतिशील हरियाणा के लिए मिलकर कार्य करने के लिए समस्त सदन के सहयोग की अपील करता हूँ।

[कैप्टन अभिमन्यु]

निष्कर्ष

माननीय अध्यक्ष महोदय

140. यह बजट एक ऐसी मुश्किल घड़ी के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है जब राज्य अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि, सरकार इस कठिनाई को अवसरों में बदलने और हरियाणा को किसानों, गण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्रीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ बदलने के प्रति आश्वस्त है।

अटल जी की कविता का एक पैरा मैंने पहले पढ़कर सुनाया है और एक पैरा मैं अब पढ़कर सुनाता हूं–

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा अति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।

141. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों को इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

वंदे मातरम!

जय हिन्द!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 22 मार्च, 2016 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*16.21 बजे **(तत्पश्चात सभा मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थागित) की गई।**

© 2013

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.